सर्वहारा दृष्टिकोण

डिजिटल संस्करण
इंटरनेट के जरिये वितरण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) SUCI (C) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-41 अंक 3 | 7 से 21 फरवरी 2026 | मुख्य संपादक: कॉमरेड प्रभास घोष | कुल पृष्ठ : 8 | मूल्य : 4 रुपये | पृष्ठ 1

बेंगलुरु में आयोजित जन संसद ने पारित की जन शिक्षा नीति-2026

बेंगलुरु (कर्नाटक) : यूजीसी के पूर्व चेयरमैन प्रो. सुखदेव थोराट ने 24 जनवरी को यहां रामैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एपेक्स ऑडिटोरियम में आयोजित जन संसद का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम एनईपी-2020 के विकल्प के तौर पर ''जन शिक्षा नीति'' बनाने के लिए आयोजित किया गया था।

कार्यक्रम में बोलते हुए प्रो. थोराट ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से सलाह किये बिना अलोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 लागू की है। यह शिक्षा के पूर्ण केंद्रीकरण की ओर बढ़ रही है। भारतीय ज्ञान प्रणाली के नाम पर अतार्किक और अवैज्ञानिक पाठ्यक्रम तैयार किये जा रहे हैं। 1990 के दशक में निजीकरण की लहर के बाद से शैक्षिक असमानता बढ़ रही है। लगभग 67% उच्च शिक्षण संस्थान स्व-वित्तपोषित और निजी हो गए हैं। बढ़ती फीस के कारण आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों में 22% ड्रॉपआउट दर देखी जा रही है। नतीजतन, 'सार्वजनीन शिक्षा' एक मृगतृष्णा बन गई है। उन्होंने एक ऐसी ''जन शिक्षा नीति'' अपनाने का आह्वान किया, जो वैज्ञानिक, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और सार्वजनीन हो और शिक्षा को एक खरीद-बेच के माल के बजाय सार्वजनिक भलाई के रूप में माने।

पूर्व सांसद और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पूर्व सचिव श्री जवाहर सरकार ने अपने लंबे प्रशासनिक अनुभव के आधार पर एक गंभीर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान आंदोलन एक अत्यंत शक्तिशाली और संगठित शक्ति के खिलाफ लड़ाई है। उन्होंने एनईपी-2020 को एक ''नौकरशाही उपकरण'' बताया, जिसे शिक्षा के चार मुख्य उद्देश्यों को लागू करने के लिए डिजाइन किया गया है: शिक्षा का केंद्रीकरण, कॉर्पोरेटीकरण, सांप्रदायीकरण और निजीकरण। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह सरकार केवल याचिकाओं पर प्रतिक्रिया नहीं देती है और आग्रह किया कि एनईपी-2020 को संसद और न्यायपालिका सहित सभी मंचों पर चुनौती दी जानी चाहिए।

बेंगलुरु: जन संसद का उद्घाटन करते हुए प्रो. सुखदेव थोराट एवं मंच पर विराजमान शिक्षा जगत की अन्य जानी-मानी हस्तियां। 24 जनवरी

जाने-माने बुद्धिजीवी और आईआईटी, बॉम्बे के सेवानिवृत्त प्रोफेसर प्रो. राम पुनियानी ने वर्तमान शैक्षिक संकट का विश्लेषण किया। उन्होंने निराशा व्यक्त की कि 11 साल सत्ता में रहने के बावजूद वर्तमान केंद्र सरकार एक सदी पुरानी राजनीतिक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका उद्देश्य सामाजिक असमानता को गहरा करना और संवैधानिक अधिकारों को दबाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां एक तरफ क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ अमीरों के लिए रिजर्व की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी स्कूल बंद किये जा रहे हैं और शिक्षकों के हजारों पद खाली पड़े हैं।

उन्होंने वैज्ञानिक सोच और तर्कसंगत विचार पर हो रहे सुनियोजित हमले की कड़ी आलोचना की। उन्होंने पाठ्यपुस्तकों से पीरियोडिक टेबल और विकासवाद के सिद्धांत को हटाने जैसे चिंताजनक बदलावों पर जोर दिया, जो एक गैर-वैज्ञानिक ''गुरुकुल मॉडल'' के पक्ष में स्थापित वैज्ञानिक बुनियादों को कमजोर करता है। उन्होंने चेतावनी दी कि सभी ऐतिहासिक प्रगति तर्कसंगत सोच की नींव पर बनी है; हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। शासकों के हमलों के कारण देश को अंधकार युग में जाने से रोकने के लिए लड़ना जरूरी है।

(शेष पृष्ठ 8 पर)

मैकॉले या वैज्ञानिक चिंतन—किस पर है भाजपा का निशाना

हाल ही में कई कार्यक्रमों में, यहां तक कि अयोध्या में राममंदिर का ध्वज फहराते समय भी नरेंद्र मोदीजी को 'मैकॉले के विचारों से उत्पन्न सामाजिक घाव' और 'औपनिवेशिक दासता से मुक्ति' की बात क्यों याद आई? 17 नवंबर को इंडियन एक्सप्रेस पत्रिका के संस्थापक रामनाथ गोयनका स्मारक व्याख्यान में भी मोदीजी ने कहा कि मैकॉले की शिक्षा पद्धति ने हमारी प्राचीन सभ्यता की नींव उखाड़ दी है, इसका सामाजिक प्रभाव एक दशक के भीतर देश से मिटाना होगा। जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव की जल्दबाजी में अधूरे राममंदिर का उद्घाटन करते समय उन्होंने और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवतजी ने कहा था कि 500 वर्षों का 'घाव भर गया'। तो फिर 'घाव भरने' के इस प्रश्न में वास्तव में नरेंद्र मोदी तथा आरएसएस-भाजपा क्या चाहते हैं?

मैकॉले साहब की बहुचर्चित शिक्षा सिफारिशों के 190 साल बाद उन्हें लेकर इतनी बातें क्यों हो रही हैं, इस पर थोड़ा गहराई से विचार करना चाहिए। सोचना चाहिए कि लक्ष्य वास्तव में मैकॉले हैं या कुछ और!

मैकॉले ने क्या किया था

थॉमस बैबिंगटन मैकॉले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनाधीन भारत में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक के सलाहकार के रूप में 1834 से 1839 तक शिक्षा और कानूनी सुधारों के काम में परामर्श देते थे। फरवरी 1835 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के अध्यक्ष के रूप में शिक्षा सुधार संबंधी विषय पर 'मैकॉले मिनट्स' में उन्होंने भारतीयों के लिए संस्कृत और अरबी माध्यम से शिक्षा का विरोध करते हुए अंग्रेजी में शिक्षा देने की बात कही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जरूरत थी कि कुछ अंग्रेजी शिक्षित क्लर्क तैयार हों। इसलिए मैकॉले ने अपनी सिफारिश 'मैकॉले मिनट्स' में लिखा कि जरूरत है अंग्रेजी शिक्षित ऐसे लोगों की जो 'खून और रंग से भारतीय' हों, लेकिन 'रुचि, विचारधारा, नीति और सोच में अंग्रेज'। लेकिन, उस समय जिन्होंने अंग्रेजी सीखी, क्या वे सब मैकॉले द्वारा वर्णित ऐसे ही लोग बने? साथ ही यह भी सोचना चाहिए कि आज जो लोग तथाकथित 'स्वदेशी-विदेशी' का लेबल हटाकर अंग्रेजी भाषा शिक्षा के पक्ष में हैं, ज्ञान की खोज में विश्व के तमाम उन्नत ज्ञान की साधना में प्रवृत्त हैं, जो इतिहास की वैज्ञानिक दृष्टि और वैज्ञानिक-लोकतांत्रिक शिक्षा चाहते हैं, जो स्वदेशीपन के बहाने विश्व से प्राप्त श्रेष्ठ आदर्शों को त्यागने को तैयार नहीं हैं—क्या वे सभी आरएसएस-भाजपा के कथित 'भारतीय परंपरा-विरोधी' 'मैकॉले की संतान' हैं?

हालांकि इतिहास कहता है कि अंग्रेज शासक स्वयं भारतीयों को अंग्रेजी सिखाने में संकोच करते थे। 1831 में ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स में मेजर जनरल लियो स्मिथ ने भारत में शिक्षा विस्तार के संदर्भ

(शेष पृष्ठ 2 पर)

बिजली (संशोधन) विधेयक-2025 पर केन्द्रीय उर्जा सचिव के साथ वार्ता के लिए बुलाये गये बिजली उपभोक्ताओं के संगठन

16 जनवरी, 2026 को केंद्र सरकार के बिजली सचिव द्वारा ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स एसोसिएशन और ऑल बंगाल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स एसोसिएशन को एक ऑनलाइन मीटिंग के लिए बुलाया गया। चर्चा का विषय बिजली (संशोधन) बिल 2025 था।

बिजली उपभोक्ता आंदोलन की अखिल भारतीय कमेटी, 'ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स एसोसिएशन' (एआईईसीए) से महासचिव के. वेणुगोपाल भट्ट और 'ऑल बंगाल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स एसोसिएशन' (एबीईसीए) से महासचिव सुब्रत विश्वास ने इस चर्चा में हिस्सा लिया।

देश के बिजली कारोबारी इजारेदार उद्योगपतियों, विभिन्न राज्य सरकारों, बिजली वितरण कंपनियों के प्रतिनिधियों, कई एनजीओ और ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स एसोसिएशन व ऑल बंगाल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने बिजली उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों के तौर पर इस बैठक में हिस्सा लिया। देश के बिजली उपभोक्ताओं (घरेलू, छोटे बिजनेस, छोटे उद्योग और छोटी खेती) की तरफ से सिर्फ उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों ने पूरे बिल के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने बिजली उपभोक्ताओं और जनता के फंड से बने बिजली क्षेत्र के हित में ये बातें उठाईं।

उन्होंने बताया कि 1) यह बिजली (संशोधन) बिल 2025 देश की सभी राज्य सरकार की बिजली वितरण कंपनियों के पूरी तरह निजीकरण के लिए बनाया गया है।

2) क्योंकि बिजली एक जरूरी सेवा है और इसे सरकारी खजाने से शुरू किया गया था, इसलिए इसे मुनाफे के लिए व्यावसायिक वस्तु नहीं माना जाना चाहिए।

3) इस संशोधन बिल में अगले पांच सालों में तथाकथित क्रॉस-सब्सिडी को पूरी तरह खत्म करने का सुझाव आम बिजली उपभोक्ताओं और किसानों के लिए एक बहुत बुरा प्रस्ताव है।

4) यह बिल 'यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन' सिस्टम को पूरी तरह खत्म करने और एक ही इलाके में कई बिजली वितरण कंपनियों को काम करने के लिए लाइसेंस देने का प्रस्ताव करता है। प्राइवेट मालिकों द्वारा बड़े पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके मुनाफा कमाने की यह व्यवस्था आम बिजली उपभोक्ताओं के हितों को खतरे में डाल देगी। निजी मालिक केवल उन्हीं इलाकों में बिजली वितरण का काम करेंगे, जहां ज्यादा मुनाफा हो, जिससे सरकारी बिजली वितरण कंपनियों को गहरे

(शेष पृष्ठ 7 पर)

मैकाले....

(पृष्ठ 1 का शेष)

में कहा था: 'शिक्षा का विस्तार हमें उस देश से बाहर कर देगा' (लाइफ एंड लेटर्स ऑफ लॉर्ड मैकॉले)। मैकॉले ने भी लिखा था कि 'ग्रीक और लैटिन का स्पर्श न मिलने पर अंग्रेजी भाषा का विकास संभव नहीं था'। उसी तरह अंग्रेजी भारतीय भाषाओं को भी विकसित करने में मदद कर सकती है। क्योंकि उन्नत भाषा ही उन्नत चिंतन का आधार होती है, इसलिए इससे भारत में ज्ञान-विज्ञान की साधना का विस्तार हुआ, धार्मिक संकीर्णता और जातिवाद के खिलाफ चिंतन विकसित होने में मदद मिली। वास्तव में देखा गया कि अंग्रेजी भाषा शिक्षा ने भारतीयों के सामने आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के द्वार खोल दिये और भारतीय नवजागरण के उदय की स्थिति बनायी। उसकी निरंतरता में बाद में ब्रिटिश-विरोधी भारतीय राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता आंदोलन उभरकर आया।

भारतीयों की ही थी अंग्रेजी सीखने की मांग

वास्तव में, उस समय भारतीयों के सामने अंग्रेजी शिक्षा का द्वार खोलने के सिवा अंग्रेजों के पास और कोई चारा नहीं था। यह उस समय भारतीयों के भीतर से उठी एक प्रबल मांग थी। कई भारतीय उसी समय अंग्रेजी भाषा और दर्शन-विज्ञान के अनेक विषयों में यूरोपियों के समकक्ष हो गए थे, यह मैकॉले की दृष्टि से भी छिपा नहीं रहा। लॉर्ड कर्जन के समय टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक लोवाट फ्रेजर ने लिखा था: "यदि हम भारत के जनसाधारण के लिए पश्चिमी ज्ञान के भंडार का द्वार न खोलते, तो वे स्वयं उसे खोल लेते। संस्कृत साहित्य की छाया से ढके प्राचीन वन में विचरण करके वे अब संतुष्ट नहीं रह सकते थे। पश्चिम हमेशा ही अपने प्रवेश के सामने सभी बाधाओं को पारकर आगे बढ़ा है–हमारे विरोध का सिंहद्वार उन्होंने जिस चाबी से खोल दिया, उसे हम छीनने की कोशिश कर सकते थे। लेकिन हमारे पास और कुछ करने को नहीं था। 30 करोड़ लोगों को मानसिक गुलामी के बंधन में बांधकर नहीं रखा जा सकता।" (India Under Curzon and After, Lovat Fraser, 1911, p-188)।

इसलिए मैकॉले तो मात्र निमित्त थे, संपूर्ण ब्रिटिश शक्ति कोशिश करती तब भी भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा से वंचित नहीं रख सकती थी। राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर सहित भारतीय नवजागरण के मनीषियों के प्रयास से क्लर्क बनाने वाली शिक्षा के स्थान पर आधुनिक इन्सान बनाने की शिक्षा के लिए संघर्ष शुरू हुआ।

आधुनिक इन्सान कौन

राजा राममोहन राय ने 1822 में अपने स्थापित एंग्लो हिंदू स्कूल और 1826 में वेदांत कॉलेज में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा प्रणाली के पक्ष में आवाज उठायी। उन्होंने लिखा: "संस्कृत शिक्षा व्यवस्था देश को अंधकार में डुबाए रखने की एक योजनाबद्ध चाल है" (लॉर्ड एमहर्स्ट को लिखे पत्र में)। उन्होंने संस्कृत, अरबी और फारसी के स्थान पर अंग्रेजी, आधुनिक विज्ञान, रसायनशास्त्र आदि पढ़ाने की बात कही।

ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने 1852 में अपने 'संस्कृत कॉलेज पर नोट' में लिखा था: "यदि संस्कृत कॉलेज के छात्रों को अंग्रेजी साहित्य अच्छी तरह पढ़ाया जाए, तभी वे समृद्ध बांग्ला साहित्य के दक्ष और शक्तिशाली लेखक बन सकते हैं।" उन्होंने संस्कृत में गणित के स्थान पर अंग्रेजी में आधुनिक गणित पढ़ाने की बात कही थी। उन्होंने बंगाल के शिक्षकों से कहा कि वे अंधविश्वास-मुक्त हों और अंग्रेजी व बांग्ला दोनों भाषाओं में दक्ष हों। विद्यासागर चाहते थे कि अंधविश्वास में डूबे समाज की जड़ें उखाड़कर मध्ययुगीन विचारधारा, धार्मिक संकीर्णता से लैस इन्सान पैदा करने का दौर का अंत कर आधुनिक चिंतन से लैस आधुनिक इन्सान का विकास किया जाए। इसी कारण उन्होंने अंग्रेजी भाषा शिक्षा और आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की साधना का समर्थन किया था।

मैकॉले द्वारा वर्णित 'अंग्रेजी सांचे में ढले' इन्सान बनाने के बजाय आधुनिक भारतीय बनाने के लिए इन दोनों मनीषियों सहित और भी कई लोगों ने संघर्ष किया। आधुनिकता का अर्थ यूरोप की नकल करना नहीं, बल्कि विश्व के सभी उन्नत विचारों का तार्किक आत्मसात करना है। इस बात को उन्होंने स्थापित किया। इसी मार्ग से उग्रता-मुक्त स्वराष्ट्रबोध विकसित हुआ, जिसने राष्ट्रवादी आंदोलन के मार्ग में प्रकाश स्तंभ का काम किया। भारत के आजादी आंदोलन के नेता, वैज्ञानिक, साहित्यकार, कलाकार आदि, जिन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठायी, उनमें से किसी ने भी प्राचीन भारत की श्रेष्ठता का हवाला देकर आधुनिक ज्ञान-विज्ञान से मुंह नहीं मोड़ा।

ज्योतिबा फुले, रवींद्रनाथ टैगोर, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, भगत सिंह, सुभाषचंद्र बोस, मेघनाद साहा आदि, जिन पर भारतवासी गर्व करते हैं–उन सभी के मामले में यह बात सच है।

फिर भी मध्य प्रदेश के भाजपा नेता और शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि 'अंग्रेजों के दलाल' के रूप में राममोहन ने हिंदुओं के धर्मांतरण में अंग्रजों की मदद की। इससे पहले 2019 में सती प्रथा के समर्थन में खड़ी होकर भाजपा-समर्थक अभिनेत्री पायल रोहतगी और राजस्थान की भाजपा नेत्री विजय राजे सिंधिया ने भी राममोहन को अंग्रजों का 'चमचा' कहा था। आरएसएस-भाजपा की यही स्पष्ट स्थिति है। यहां तक कि पश्चिम बंगाल में भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बंगालियों को रवींद्रनाथ-नजरुल की चर्चा से बाहर आना चाहिए। पश्चिम बंगाल भाजपा के तथा विपक्षी दल के नेता चाहते हैं कि नजरुल का गीत "एक ही डाली के दो फूल" हटा दिया जाए। तो फिर किस राष्ट्रीयता के आधार पर भाजपा कथित स्वदेशी विचार कायम करेगी?

कैसा स्वदेशीपन चाहती है भाजपा

भारतीय परंपरा और राष्ट्रीयता से भाजपा क्या समझाना चाहती है? 2014 में केंद्र सरकार में आने के बाद से आरएसएस कथित 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' के कार्यक्रम को शिक्षा क्षेत्र में लागू करने की कोशिश कर रहा है। उसके अनुसार इस राष्ट्रवाद का आधार है 'शुचिता', 'सुरक्षा', 'स्वदेशी', 'सामाजिक समान मार्ग' और 'हिंदुत्व'। इस एजेंडे को शिक्षा क्षेत्र में प्रवेश कराने के लिए पहले गुजरात की भाजपा सरकार ने 'प्रेरणा दीप' नामक एक पुस्तक सहित नौ पुस्तकें स्कूल स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल कीं। इनमें महाभारत में स्टेम सेल अनुसंधान, टेलीविजन का आविष्कार, वैदिक युग में मोटर गाड़ी का आविष्कार जैसी बातें थीं। साथ ही स्वदेशीपन के नाम पर अफ्रीका के अश्वेतों को भारतीयों की तुलना में कम बुद्धि वाला दिखाना और विवेकानंद विदेशियों को जूते के बराबर मानते थे जैसी गपें थीं। उनके पृष्ठपोषण में वैदिक विमान और मंगल ग्रह पर भारतीय वैदिक ऋषियों के 'हेलमेट' पहनने की कल्पना से भरा पेपर विज्ञान कांग्रेस में पढ़ा गया। क्या यही भारतीय परंपरा का असली नमूना है? वे विज्ञान शिक्षा में भी डार्विन के विकासवाद के खिलाफ नारा लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वयं गणेश के सिर की तुलना प्लास्टिक सर्जरी से करके अवैज्ञानिक हास्यास्पद बातें कह चुके हैं। रामायण के वास्तविक इतिहास को भुलाकर भारतीय इतिहास के इस महत्वपूर्ण तत्व को वे सांप्रदायिक उद्देश्य से इस्तेमाल कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी भाजपा ने वैदिक गणित और ज्योतिष को शामिल किया है। वे आईआईटी जैसे विज्ञान शिक्षा के महत्वपूर्ण संस्थानों से अवैज्ञानिक और धार्मिक अंधविश्वासपूर्ण विचारों का प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। साहित्य के पाठ्यक्रम में भी आरएसएस द्वारा चयनित कुछ लेखकों की रचनाओं को छोड़कर नवजागरण की सोच से युक्त मानवतावादी और साम्राज्यवाद-विरोधी मनीषियों की रचनाएं हटायी जा रही हैं। याद रखना चाहिए कि भाजपा 'भारतीय ज्ञान प्रणाली' के नाम पर प्राचीन भारत की गौरवगाथा का जो प्रचार करना चाहती है, उसका पहले ही अक्षय कुमार दत्त, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, मेघनाद साहा जैसे चिंतक-वैज्ञानिकों ने कड़ा विरोध किया था। रवींद्रनाथ ने 'प्रत्नत्व' नामक रचना सहित अनेक लेखों में इन मिथकों पर तीव्र प्रहार किया था। क्या भाजपा इन्हें आधुनिक इन्सान मानेगी? वे तो वेद-पुराण-वेदांत की शिक्षा से बाहर आकर अंग्रेजी भाषा, मातृभाषा और ज्ञान-विज्ञान की साधना की बात कर रहे थे। क्या भाजपा उन्हें भी मैकॉले का अनुयायी मानती है?

सांप्रदायिक धर्म के ध्वजधारियों ने ही की थी अंग्रेजों की ज्यादा गुलामी

अंग्रेजों की भक्ति सबसे ज्यादा किन लोगों ने की? यह काम उन लोगों ने किया, जिन्होंने धार्मिक कट्टरता को लेकर चलते हुए तथाकथित प्राचीन भारतीय परंपरा के पुजारी के रूप में टोल-मदरसा शिक्षा का समर्थन किया और अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया। जैसे, 1919 में 'पंजाब हिंदू सभा' ने जलियांवाला बाग में अंग्रेज हुकूमत द्वारा किये गये जनसंहार के बाद अंग्रेजों के बजाय सत्याग्रहियों की निंदा की और अंग्रेजों के प्रति 'गहरी निष्ठा' की शपथ ली। (के एल टुटेजा – The Punjab Hindu Sabha and Communal Polity, 1906–1923, Frontline, 14 मार्च 2003 – विश्वमोहन झा के लेख में उद्धृत)। हिंदू-मुस्लिम दोनों धर्मों के प्रभावशाली धनी और अभिजात वर्ग के लोग शुरू से ही नवजागरण और उससे उत्पन्न भारतीय स्वदेश चेतना के विरोधी थे। अंग्रेजी हुकूमत की अंग्रेजी शिक्षा की पहल का विरोध 1870 में विंगर के राजा शिवप्रसाद, बनारस के राजा आदि हिंदू सामंतों ने किया। उसी तरह 1888 में सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजी पढ़ाने का विरोध किया (आधुनिक भारत और सांप्रदायिकता, बिपन चंद्र)। यही धनी अभिजात वर्ग बाद में मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, आरएसएस आदि सांप्रदायिक संगठनों का प्रमुख पृष्ठपोषक बना। उल्लेखनीय है कि नागपुर सहित विस्तृत क्षेत्रों में महान मानवतावादी ज्योतिबा फुले ने जातिवाद के खिलाफ और शिक्षा विस्तार के लिए जो 'सत्यशोधक' आंदोलन खड़ा किया, उसके प्रभाव से सामाजिक क्षेत्र में तथाकथित दलितों, अछूतों का महत्व बढ़ने लगा। इसके खिलाफ प्रतिक्रिया की शक्ति के रूप में उच्चवर्ण का प्रभुत्व बनाये रखने और मुस्लिम-विरोधी नारा लगाकर 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई। आरएसएस ने शुरू से ही संस्कृत शिक्षा के माध्यम से 'भारतीयता' बचाने की बात कहकर 'विदेशी' अंग्रेजी भाषा शिक्षा का विरोध किया। जबकि आरएसएस की विचारधारा वास्तव में इटली-जर्मनी के फासिस्टों से ली गयी है। जो आरएसएस अब 'औपनिवेशिक दासता दूर' करने और 'मैकॉले की संतान' खोजने निकला है, उसका इतिहास तो लगातार अंग्रेजों की चाटुकारिता का रहा है। आरएसएस के गुरु गोलवलकर ने ब्रिटिश-विरोधी आजादी आन्दोलन को प्रतिक्रियावादी कहा था (गोलवलकर, विचार नवनीत)। उनके पूज्य बी डी सावरकर का ब्रिटिश को दिया गया माफीनामा और बाद में अंग्रेजों की चाकरी का इतिहास तो भुलाया नहीं जा सकता।

स्वदेशीपन का मुखौटा

आरएसएस-भाजपा संचालित केंद्र सरकार ने तथाकथित 'औपनिवेशिक दासता' से मुक्ति का क्या उपाय किया है? 2014 से आरएसएस संचालित 'विद्याभारती', 'अखिल भारतीय विद्या संस्थान द्वारा संचालित स्कूलों की पाठ्यपुस्तकों में भारत के मानचित्र में नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान, तिब्बत सभी देशों को शामिल दिखाया गया है। हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के नाम क्रमशः हिंदू महासागर, सिंधु सागर और गंगा सागर रखे गए हैं। यहां तक कहा गया है कि ग्रीक कवि होमर ने रामायण और महाभारत पढ़कर और उसका अनुसरण करके महाकाव्य लिखा! यहां तक कि बुद्ध ने गीता से ही अपना धर्ममत सूत्रबद्ध किया और ईसा मसीह हिमालय में आकर हिंदू साधुओं से धर्म शिक्षा लेकर ईसाई बने (आनंदबाजार पत्रिका, 11.11. 1998)। क्या यह शिक्षा सही शिक्षा है? इससे जिस तरह का 'स्वदेशीपन' जागेगा, क्या वह वास्तविक स्वदेश चेतना होगी? भारतीय परंपरा के नाम पर भाजपा ने संस्कृत शिक्षा के लिए दस वर्षों में 2,532 करोड़ 59 लाख रुपये खर्च किये। लेकिन बाकी पांच शास्त्रीय भाषाओं के लिए कुल मिलाकर सिर्फ 147 करोड़ रुपये आवंटित किये। साथ ही भाजपा द्वारा बनायी गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अंग्रेजी भाषा शिक्षा का महत्व सामान्य सरकारी स्कूलों में कम करने की कोशिश की है। जबकि राममोहन और विद्यासागर से लेकर इस देश के अधिकतर मनीषियों और स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी के महत्व को कम करने और संस्कृत शिक्षा पर अत्यधिक जोर देने का विरोध किया है। यहां तक कि हिंदू धर्म के प्रमुख प्रवक्ता स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं: "हमारी भाषा संस्कृत की मंथर गति की चाल है–उसी चाल की नकल करके चीजें अस्वाभाविक हो रही है" (भावबार कथा, स्वामी विवेकानंद)। शोध के लिए कोई संस्कृत का अध्ययन कर सकता है, लेकिन 'हिंदुत्व' के नाम पर संस्कृत को आधुनिक भाषाओं पर थोपकर मातृभाषा और अंग्रेजी शिक्षा का मार्ग अवरुद्ध करने का विरोध करना जरूरी है। दूसरी ओर, आरएसएस के 'हिंदी-हिंदू-हिंदुस्तान' एजेंडे के अनुसार मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने हिंदी में एमबीबीएस पढ़ाने के लिए 10 करोड़ रुपये खर्चकर किताबें छापी हैं। लेकिन वे पूरी तरह पड़ी हुई हैं, क्योंकि राष्ट्रीयता के नाम पर विश्व की चल रही धारा से अलग होकर आधुनिक शिक्षा संभव नहीं है–यह छात्र-शिक्षक गहराई से समझ चुके हैं। आज अफगानिस्तान के तालिबान या भारत-पाकिस्तान -बांग्लादेश के मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा धर्म रक्षा, परंपरा, राष्ट्रीय श्रेष्ठता के नाम पर जो नारे लगाये जाते हैं, उनसे आरएसएस-भाजपा की इन कोशिशों का अंतर कहां है?

तीर असल में किस ओर

मैकॉले के विचारों से मुक्त होकर स्वदेशी होने की बात करने वाले मोदीजी के इस्तेमाल किये गए पेन, चश्मे और घड़ी से लेकर अधिकतर चीजें विदेशी बतायी जाती हैं। वे 'वोकल फॉर लोकल' कहते हुए

(शेष पृष्ठ 7 पर)

''अत्यधिक गरीबी'' से मुक्त है केरल
–सीपीआई (एम) सरकार का दावा

सीपीआई (एम)-नीत केरल सरकार ने गर्व से दावा किया है कि उसने राज्य से अत्यधिक गरीबी को खत्म कर दिया है। यह घोषणा 1 नवंबर को केरल स्थापना (पिरवी) दिवस पर की गई। अपने दावे के समर्थन में सीपीआई (एम)-नीत सरकार ने कहा है कि 2021 में 'अत्यधिक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (ईपीईपी)' शुरू करने से पहले, कथित तौर पर 64,006 परिवार अत्यधिक गरीबी में जी रहे थे। लेकिन विभिन्न गरीबी उन्मूलन योजनाओं को लागू करके उनको अत्यधिक गरीबी के स्तर से ऊपर उठाया गया है। मंत्री एम. बी. राजेश के अनुसार, इन 64,006 परिवारों की पहचान स्थानीय स्व-शासन संस्थानों के माध्यम से किये गए एक सर्वेक्षण द्वारा की गई थी।

अत्यधिक गरीबी की परिभाषा

विश्व बैंक ने (2017 पीपीपी के आधार पर) प्रति दिन 2.15 डॉलर (लगभग 193 रुपये) से कम आय पर जीवन यापन करने वाले को अत्यधिक गरीब के रूप में परिभाषित किया है। हालांकि भारत सरकार मानती है कि प्रति दिन 1.25 डॉलर (112.50 रुपये) से कम आय वाला कोई भी व्यक्ति ''अत्यधिक गरीबी'' में रहता है। अगर कैलोरी खपत के मानदंडों को देखें, तो पुरुषों के मामले में प्रति दिन 2,400 कैलोरी से कम और महिलाओं के मामले में 2,100 कैलोरी से कम प्राप्त करने वाले लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। अगर भोजन सेवन के संदर्भ में देखा जाए, तो 2400 कैलोरी का सेवन ऐसे आहार से किया जा सकता है, जो एक आम भारतीय के लिए अकल्पनीय है, जो प्रति दिन 200 रुपये भी कमा सकता है। इसलिए कमाई के स्तर के मानदंडों और कैलोरी खपत-आधारित मानदंडों के बीच बेमेल बहुत अधिक है।

केरल का परिदृश्य

30 सितंबर 2024 को केरल के एक मंत्री जी. आर. अनिल ने विधानसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि राज्य में 5,91,194 अत्यंत गरीब व्यक्तियों को 'अंत्योदय अन्न योजना' के तहत एएवाई पीले कार्ड जारी किये गए हैं।

लगभग 4.5 लाख आदिवासी और जनजातीय समुदाय हैं जैसे कि पनिया, आदिया, कट्टुनायका और वेट्टाकुरुमा, जिनकी गरीबी और मुसीबतों का बखान करना मुश्किल है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ में 2022 में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया है कि वायनाड जिले में पांच साल से कम उम्र के 54.8 प्रतिशत बच्चे गंभीर रूप से कुपोषण से पीड़ित हैं। अट्टापडी में भी हालात कुछ अलग नहीं हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के एक अध्ययन के मुताबिक, वहां 48 प्रतिशत बच्चे कम वजनी है, जबकि 40 प्रतिशत बच्चों का कद बढ़ना मारा गया है। अध्ययन में आगे बताया गया कि 91 प्रतिशत बच्चे, 96 प्रतिशत कमसिन लड़कियां और 80 प्रतिशत गर्भवती औरतें एनीमिया (खून की कमी) से ग्रस्त हैं।

पौधा रोपण में कार्यरत मजदूर, मछुआरे, तथाकथित दलित समुदाय, आशा वर्कर और दूसरी स्कीम वर्कर भी ऐसी ही मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। नाबार्ड के एक सर्वेक्षण में पहले ही बताया गया है कि राज्य की 65 फीसदी आबादी इतनी आय नहीं कमाती कि वह इज्जतदार जिंदगी जी सके।

लेकिन अगर केरल सरकार से पूछा जाए, तो उसका जवाब होगा कि वे सभी सिर्फ गरीब हैं–लेकिन अत्यधिक गरीब नहीं हैं। ऐसा इसलिए है कि सरकार ने अत्यधिक गरीबी को परिभाषित करने के लिए नए-नए और बहुत ज्यादा रोक-टोक लगाने वाले पैमाने अपनाने शुरू कर दिये हैं। जिनके पास कोई भी आमदनी नहीं है, जो दिन में दो वक्त के खाने तक का खर्च वहन नहीं कर सकते, जो राशन मिलने पर भी खाना नहीं पका सकते और जिनकी सेहत पूरी तरह से खराब हो गई है–सिर्फ उन्हें ही सरकार *अत्यधिक गरीब* मानती है। लेकिन अगर "जो लोग दिन में दो जून के खाने का खर्च वहन नहीं कर सकते" उन्हें अत्यधिक गरीबों में गिना जाता है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि जो लोग दिन में सिर्फ एक जून के खाने का खर्च वहन कर पाते हैं, वे न तो अत्यधिक गरीब हैं और न ही दीन-हीन? अर्थशास्त्रियों ने ठीक ही पूछा है कि क्या ऐसे लोगों को सिर्फ गरीब माना जाना चाहिए या बिल्कुल ही परित्यक्त। असल में, सरकार ने जो किया है, वह यह है कि उसने अत्यधिक गरीबों में से दीन-हीन लोगों के एक छोटे से हिस्से को अत्यधिक गरीबी से मुक्त हुए घोषित कर दिया है। सच तो यह है कि राज्य के सभी दीन-हीन लोगों को उस सूची में फिर भी जगह नहीं मिली है।

घोर गरीबी झेल रहे लाखों लोगों के लिए कैलोरी के हिसाब से भोजन मर्मस्पर्शी ढंग से बहुत ही अपर्याप्त है। क्या सरकार सच में यह दावा करती है कि अत्यधिक गरीब परिवारों को महीने में एक बार अनाज का किट बांटने से ही अत्यधिक गरीबी खत्म हो गई है–एक किट, जो असल में अक्सर दो या तीन महीने में एक बार ही उन तक पहुंचता है? अगर ऐसा है, तो यह दावा एक क्रूर मजाक से कम नहीं है।

अत्यधिक गरीब परिवार या एएवाई पीले-कार्डधारक हर महीने 35 किलोग्राम अनाज पाने के हकदार हैं। लेकिन सिर्फ इसी से उनके जीवन-निर्वाह के बुरे हालात नहीं बदलते। यह सच है कि उन्हें इलाज और दूसरी जरूरतों के लिए कुछ छोटे-मोटे फायदे भी मिलते हैं। फिर भी, केरल अब अत्यधिक गरीबी से मुक्त है–यह एलान अगर ऐसी हालत पैदा कर देता है कि केंद्र सरकार से जो थोड़ा-बहुत राशन मिलता है, वह भी वापस ले लिया जाए, तो इसका क्या अंजाम होगा? क्या केरल में वाम जनवादी मोर्चे की सरकार केंद्र सरकार के लिए ऐसी समाज कल्याण स्कीम को खत्म करने का रास्ता खोल रही है?

एलान का तमाशा, हाथों में भीख का कटोरा

इस एलान की और भी परेशान करने वाली बात यह है कि राज्य सरकार ने यह एलान बड़ी धूमधाम से करने की राह चुनी है। जिस समारोह में यह एलान किया गया, उसे आयोजित करने में 1.5 करोड़ रुपये तक खर्च किये गए। कहा जाता है कि यह रकम उन 52.8 करोड़ रुपयों में से बांटी गई थी, जो असल में गरीबों के लिए शेल्टर बनाने के लिए तय की गई थी। इसमें से हिस्सा देने का आदेश स्थानीय स्व–शासन विभाग ने 26 अक्टूबर को बिना किसी जमीर की कचोट के जारी किया था।

इन विज्ञापनों के जरिये पिनारयी सरकार ने केरल की छवि को झूठमूठ एक खुशहाल राज्य के तौर पर पेश करने की कोशिश की। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन और उनके संगी-साथियों ने 1 नवंबर को यह एलान किया कि राज्य अत्यधिक गरीबी से मुक्त हो गया है, जबकि उन्होंने चंद मुट्ठीभर बेहद अमीर खासो-आम हस्तियों को अपने इर्द-गिर्द रखा था–यह एलान हजारों लोगों की मौजूदगी में किया गया, जिनके पास गुजारे के लिए जरूरी चीजें भी नहीं हैं। क्या हम ऊपर बताये गए कैलोरी मानदंड के आधार पर यह मान लें कि केरल में कोई भी कुपोषण से ग्रसित नहीं है?

उनका हिसाब-किताब यह हो सकता है कि विकास के ऐसे खोखले एलानों से चुनाव से ठीक पहले सीपीआई (एम)-नीत सरकार को शॉर्ट-टर्म राजनीतिक फायदा हो सकता है। हाल ही में हुए नगर निगम चुनावों में सीपीआई (एम) और उसके गठबंधन के सहयोगियों को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इसलिए विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने और सत्ता में बने रहने के लिए सीपीआई (एम)-नीत मोर्चा सच्चाई को छिपाने और तरक्की की गुलाबी तस्वीर दिखाने में हिचकिचाती नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे भाजपा, कांग्रेस और विभिन्न राज्यों की दूसरी पूंजीवादी सरकारें करती हैं। लगभग आये दिन अखबारों में विभिन्न राज्य सरकारों के विज्ञापन देखने को मिल जाएंगे, जिनमें बताया जाता है कि कैसे विकास की बयार ने उनके राज्य को चार चांद लगा दिये हैं और अच्छे दिन ला दिये हैं। लेकिन सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके जारी किये गए ऐसे विज्ञापन असमानता सूचकांक और दूसरे आंकड़ों के हिसाब से करोड़ों मेहनतकशों के गिरते जीवन स्तर के साथ एक क्रूर मजाक हैं। जैसे वे झूठी कहानी फैला रहे हैं, वैसे ही सीपीआई (एम) की केरल सरकार भी अपनी ही तारीफों के पुल बांध रही है, यह अच्छी तरह जानते हुए कि जो बातें इतने शान-शौकत से बतायी जा रही हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। यह बड़ा झूठ फैलाने के लिए कि केरल अत्यधिक गरीबी से मुक्त हो गया है, केरल सरकार ने दिखावा करने के लिए राष्ट्रीय मीडिया में भी बड़े-बड़े विज्ञापन दिये हैं। लेकिन ऐसी सरकार से और क्या उम्मीद की जा सकती है, जो अति-अमीरों की चापलूसी करती है, उनके लिए कॉन्क्लेव आयोजित करती है और यूसुफ अली जैसे कॉर्पोरेट दिग्गजों को राज्य का ब्रांड एंबेसडर बनाती है?

शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में विकास का झूठा दावा

इससे पहले, सीपीआई (एम) की केरल सरकार ने हाल ही में दावा किया था कि शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में बहुत ज्यादा तरक्की हुई है। लेकिन आम लोगों को पता है कि ऐसे अजीब दावे उनके रोज के अनुभवों से कितने अलग हैं। 201 स्कूल बंद कर दिये गए हैं। 47 स्कूलों में कोई छात्र नहीं है। 70% से ज्यादा कॉलेज प्राइवेट तौर पर (सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त) प्रबंधन में चलाये जा रहे हैं। हाल ही में नए प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल (2025) पर फोकस किया जा रहा है, जो निजी क्षेत्र में उच्च शिक्षा को देने में और बढ़ोतरी का इशारा दे रहे हैं, खासकर इंजीनियरिंग, आर्ट्स, साइंस और मेडिसिन जैसे क्षेत्र में, कुछ खबरों में तो अकेले दर्जनों प्राइवेट मेडिकल कॉलेज दिखाये गए हैं। केरल के सरकारी स्कूलों में पिछले दो सालों में छात्रों के दाखिले में भारी गिरावट आयी है और लगभग 50,000 छात्र स्कूल छोड़ चुके हैं। यहां तक कि जिला प्राइमरी शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) जैसी शिक्षा संबंधी परियोजनाएं भी गरीबी हटाने की रणनीति से जुड़ी हुई थीं। प्रधानमंत्री मोदी की भाजपा सरकार, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए कौशल विकास (स्किल डेवलपमेंट) को बढ़ावा देती है और केरल में पिनारयी विजयन की सीपीआई (एम)-नीत मोर्चा सरकार, जो चार साल के अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम के जरिये रोजगार आधारित शिक्षा की वकालत करती रही है, दोनों ही धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक और जनवादी शिक्षा को खत्म करने के एक ही वैश्विक पूंजीवादी एजेंडे को लागू करने वाले के तौर पर काम करती हैं।

हाल की अखबारों की खबरें और लेखे-जोखे बताते हैं कि केरल ऐतिहासिक रूप से भारत में स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक मॉडल रहा है, लेकिन इसकी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था अभी बड़ी चुनौतियों से जूझ रही है, जिसमें अधिसंरचना की कमी, साजो-सामान की कमी, स्टाफ की कमी और नागरिकों की जेब जितने की इजाजत देती है, उससे ज्यादा खर्च शामिल हैं। इस वजह से कुछ आलोचकों और एक सरकारी लेखा-परीक्षण ने व्यवस्था को गिरावट या "खराब" हालत में बताया है। पब्लिक सेक्टर की गिरावट ने निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य देखभाल के विकास और व्यापारीकरण को बढ़ावा दिया है, जिसके बारे में कुछ लोगों का कहना है कि यह मुनाफाखोरी के कारण है और आम लोगों की जरूरतों के हिसाब से नहीं है। केरल विधानसभा ने हाल ही में संक्रामक बीमारियों से होने वाली मौतों में खतरनाक बढ़ोतरी पर गरमागरम बहस की। जैसे वे यह झूठी कहानी फैलाते हैं कि केरल ने शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के मामले में बहुत तरक्की की है, वैसे ही जो लोग खुद को कम्युनिस्ट कहते हैं, वे समाज को–और अपने कार्यकर्ताओं को–यह कहकर क्या राजनैतिक पैगाम दे रहे हैं कि इस राज्य से गरीबी खत्म हो गई है? क्या सीपीआई (एम) और उसके मोर्चे के संगी-साथी इतने नासमझ हैं कि वे सबसे बुनियादी सबक भी भूल गए हैं कि यह पूंजीवादी व्यवस्था है, जो अब सामाजिक विकास के अटल नियम का पालन करते हुए अपनी मौत के मुंह में है और लोगों की जिंदगी में गरीबी, भुखमरी और दूसरी सभी परेशानियां पैदा कर रही है?

मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन ने कहा कि यह कामयाबी सबकी इच्छा से मिली है। 'नव केरलम' (नया केरल) पहल का मुख्य मकसद –जो केरलवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाकर विकसित देशों के बराबर लाना है – अब ज्यादा दूर नहीं है। उन्होंने कहा कि केरल कई मामलों में पहले से ही अमेरिका से आगे है। यही असली "केरल की कहानी" है। मुख्यमंत्री ने कहा, *"आज हमने जिस अत्यधिक गरीबी खत्म करने का एलान किया है, वह केरल के जन केंद्रित वैकल्पिक विकास मॉडल की जीत है, जिसे वह दुनिया के सामने पेश करता है। ऐसे समय में जब नव-उदारवादी नीतियां पूरे देश में असमानता बढ़ा रही हैं और पैसा सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में जमा होता जा रहा है, केरल गर्व से खड़ा है और दुनिया के सामने यह एलान कर रहा है कि समाज के सभी वर्गों को शामिल करने वाला एक दयालु, समतामवादी और कल्याणकारी मॉडल मुमकिन है।"* (पीपुल्स डेमोक्रेसी 09-11-25)

"समतावादी" शब्द पर निशान लगाएं, जिसका मतलब है इस सिद्धांत पर विश्वास करना या उस पर आधारित होना कि सभी लोग बराबर हैं और उन्हें बराबर अधिकार और मौके मिलने चाहिए। इसका मतलब है कि केरल के सीपीआई (एम) के मुख्यमंत्री के अनुसार, पूंजीवादी समाज में सरकार द्वारा सुधार के जरिये समतावादी समाज बनाना मुमकिन है। 1846 में जब महान मार्क्स ने 'जर्मन विचारधारा' नामक पुस्तक लिखी, तब उन्होंने पूंजीवादी राज्य को पूंजीवादी आर्थिक हितों का साधन मात्र बताया था। दो साल बाद, उस विचार को 'कम्युनिस्ट घोषणापत्र' में समझाया गया: *"आधुनिक (पूंजीवादी) राज्य का कार्यकारी मण्डल पूरे बुर्जुआ (पूंजीपति) वर्ग के सम्मिलित हितों का प्रबंधन करने वाली कमेटी के सिवा और कुछ नहीं है।"* सरकार, जैसा कि हर सही मार्क्सवादी जानता है, कार्यपालिका का एक अंग है, जो पूंजीवादी राज्य के तीन अंगों में से एक है। लेनिन ने कहा था: *"असल में, शासन के तरीके बहुत अलग-अलग थे, लेकिन उनका सारतत्व हमेशा एक ही था: गुलामों को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं थे और वे उत्पीड़ित वर्ग के हिस्से थे; उन्हें इन्सान नहीं समझा जाता था।"* (राजसत्ता)

इसलिए यह भ्रम पैदा करना कि कुछ सुधारों से पूंजीवादी व्यवस्था में गरीबी दूर की जा सकती है, मार्क्सवाद-लेनिनवाद के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। ■

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की 129वीं जयंती पर जगह-जगह कार्यक्रम

दिल्ली : 23 जनवरी को महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती के मौके पर, 'युद्ध का विरोध करें–शांति बहाल करें, मानवता बचायें' सप्ताह के हिस्से के तौर पर करोल बाग में पदयात्रा का आयोजन किया गया।

एआईडीएसओ के नेताओं और विभिन्न इलाकों और संस्थानों के छात्रों ने बारिश के बीच नेताजी की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर पदयात्रा शुरू की।

एआईडीवाईओ, दिल्ली के अध्यक्ष कॉमरेड अनिर्बान भौमिक, उपाध्यक्ष कॉमरेड सौम्या सामल एआईडीएसओ सदस्य और जामिया की छात्रा उज्मा और स्थानीय निवासी चंद्र प्रकाश ने सभा को संबोधित किया। वक्ताओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन-संघर्ष और मौजूदा हालात में हमारी जिम्मेदारी के बारे में चर्चा की।

स्थानीय लोगों ने कार्यक्रम पर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी और एआईडीएसओ द्वारा की गई पहल की सराहना की। लोगों ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

संगीत मंडली ने प्रगतिशील गाने पेश किये।

कार्यक्रम का संचालन एआईडीएसओ, दिल्ली राज्य सचिवमंडल सदस्य कॉमरेड बैद्यनाथ माझी ने किया।

नई बस्ती, किशनगंज, दिल्ली में 20 जनवरी को सभा का आयोजन किया गया।

दिल्ली के त्रिलोकपुरी व कोंडली क्षेत्र में एआईडीएसओ, एआईडीवाईओ, एआईएमएसएस और एआईयूटीयूसी की स्थानीय कमेटियों की तरफ से संयुक्त रूप से आजादी आंदोलन के महानायक नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जयंती शानदार ढंग से मनायी गयी। कोंडली के बी ब्लॉक पार्क में 23 जनवरी को भारी बारिश के बीच पुष्पांजलि कार्यक्रम किया गया। जबकि 25 जनवरी को त्रिलोकपुरी क्षेत्र में पहले जुलूस निकाला गया और फिर पुष्पांजलि कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का संचालन कॉमरेड धर्म देव ने किया। कॉमरेड संध्या, नवीन, बासमती, पार्वती, नीरज, नितेश, मनोज, प्रभास व जे. मुर्मू ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने नेताजी सुभाष के जीवन-संघर्ष के महत्वपूर्ण पहलू रखे। वक्ताओं ने नेताजी द्वारा अपने दौर में सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ किये गए संघर्ष का उल्लेख किया। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने काफी बड़ी संख्या में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और भरपूर मदद की।

पिलानी (राजस्थान) : नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती सम्मानपूर्वक मनाई गई। एआईकेकेएमएस व एआईडीवाईओ ने 22 जनवरी से 26 जनवरी तक पांच दिवसीय कार्यक्रम का समापन 26 जनवरी को पिलानी तालाब बस स्टैंड पर किया गया। सुबह नेताजी की तस्वीर पर एआईडीवाईओ नेता कॉमरेड विष्णु वर्मा ने माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सुबह से लेकर शाम तक नेताजी की तस्वीर पर लोग पुष्प अर्पित करते रहे। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के बैज धारण, पोस्टर प्रदर्शनी और उनके जीवन-संघर्ष पर आधारित किताबों की बुक स्टॉल लगायी गई। पूरे दिन क्रांतिकारी गीत बजते रहे। नेताजी के विचारों के पर्चे बांटे गये। शाम को कॉमरेड महादेवाराम जांगिड़ ने कार्यक्रम के समापन की घोषणा की।

कार्यक्रम में कॉमरेड राजेंद्र सिहाग, कॉमरेड शंकर दहिया, डॉक्टर रविकांत पांडे, अनवर अली भाटी, संदीप शर्मा, विकास माखरिया, होशियार सिंह, नंदलाल सैनी, महावीर प्रसाद शर्मा व अन्य कई लोग उपस्थित रहे।

भिवानी (हरियाणा) : एआईडीवाईओ और शहीद व महापुरुष यादगार कमेटी, भिवानी के बैनर तले आजादी आन्दोलन की गैर समझौतावादी धारा के महान क्रांतिकारी योद्धा नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की 129वीं जयंती पर 23 जनवरी को चेतराम प्रजापति धर्मशाला, भिवानी में यादगार सभा आयोजित की गई।

सभा की अध्यक्षता शहीद व महापुरुष यादगार कमेटी के जिला संयोजक राजकुमार बासिया ने की।

सभा का संचालन एआईडीवाईओ के जिला संयोजक कॉमरेड संदीप मेहरा ने किया। मुख्य वक्ता एसयूसीआई (सी) के राज्य सचिवमंडल सदस्य कॉमरेड रामफल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन-संघर्ष पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि देश की आजादी से उनका मतलब जुल्मी अंग्रेजी राज का खात्मा कर राजनैतिक आजादी पाने के साथ-साथ देश की जनता को हर तरह के शोषण-जुल्म से मुक्ति दिलाना और सामाजिक उत्पीड़न, गरीबी, अशिक्षा और जातपात-साम्प्रदायिकता को भी समाप्त कर नया समाज कायम करना था। वे समाजवाद के प्रबल हिमायती थे। 15 अगस्त, 1947 को देश को विदेशी शासन के जुए से राजनैतिक आजादी मिली, लेकिन शोषण से मुक्ति का नेताजी का सपना पूरा नहीं हुआ।

श्रमिक नेता धर्मबीर सिंह, किसान नेता रोहताश सिंह और राजेश कुमार दिनोद ने भी नेताजी पर अपने विचार रखे।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की याद में तोशाम के शहीद पार्क में 22 जनवरी को आयोजित सभा को मुख्य वक्ता कॉमरेड रामफल ने सबोधित किया।

रोहतक (हरियाणा) : नेताजी सुभाषचंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को एआईडीएसओ एवं एआईडीवाईओ द्वारा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण और मानसरोवर पार्क में सभा आयोजित की गई। **कैथल (हरियाणा) :** 23 जनवरी को नेताजी सुभाषचंद्र बोस यादगार सभा आयोजित की गई।

डिंडोली, सूरत (गुजरात) : 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती पर 23 जनवरी को अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रतिमा पर पुष्पांजलि कार्यक्रम किया गया।

25 जनवरी को रेलवे फाटक, डिंडोली, सूरत में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता व संचालन एआईडीवाईओ के सूरत जिला सचिव कॉमरेड सुरेशचंद्र मौर्य ने की। सभा के मुख्य वक्ता के रूप में एआईडीवाईओ, गुजरात राज्य कमेटी के अध्यक्ष कॉमरेड इंद्रजीतसिंह ग्रोवर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन-संघर्ष पर विस्तार से चर्चा की और आज के हालात में उनके विचारों की प्रासंगिकता पर जोर दिया। सभा को राम मूरत मौर्य, सत्येंद्र सिंह, बांकेलाल मौर्य, प्रयाग भाई, दिलीप मौर्य आदि वक्ताओं ने भी संबोधित किया। भावना बेन, जन्मेजय और विनोद ने क्रांतिकारी गीत प्रस्तुत किया। सभा में काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

देहरादून (उत्तराखंड) में छात्र संगठन एआईडीएसओ ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।

करहारा, पालीगंज, पटना (बिहार) : आजादी आंदोलन की गैर समझौतावादी धारा के महान योद्धा नेताजी सुभाषचंद्र बोस की जयंती यहां 31 जनवरी को मर्यादापूर्वक मनायी गई।

इसकी अध्यक्षता विमल सिंह ने की।

कार्यक्रम की शुरुआत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर पर पुष्पांजलि से हुई। छात्र-छात्राओं ने आजाद हिंद फौज में गाये जाने वाले गीत 'कदम-कदम बढ़ाये जा' और विभिन्न देशभक्ति एवं क्रांतिकारी गीतों एवं काव्यपाठ की प्रस्तुति दी। अंत में छात्र-छात्राओं को मेडल से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) की पटना जिला (ग्रामीण) सचिव कॉमरेड अनामिका ने किया। जयंती समारोह में एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के बिहार राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड सूर्यकर जितेंद्र ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने के महत्व पर प्रकाश डाला।

जयंती समारोह को संबोधित करने वालों में प्रमुख रूप से एसयूसीआई (कम्युनिस्ट)के बिहार राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड रूपेश कुमार, कॉमरेड दरबारी यादव, डॉ. राज किशोर सिंह, कॉमरेड सुनील प्रसाद आदि ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन-संघर्ष और उनके सपनों के बारे में विस्तार से चर्चा की।

अपनी ज्वलंत मांगों के लिए एनआरएलएम वर्करों ने किया प्रदर्शन

रायपुर (छत्तीसगढ़) : सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन के बराबर सम्मानजनक मानदेय देने और अपनी अन्य मांगों को लेकर एआईयूटीयूसी से जुड़े एनआरएसएलएम बिहान 'कृषि सखी पशु सखी संघ' के बैनर तले 12 जिलों की सैकड़ों महिला वर्करों ने 15 जनवरी को यहां प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया। विदित हो कि राज्य सरकार इन महिला वर्करों को भत्ते के तौर पर सिर्फ 1,910 रुपये मासिक देती है। लेकिन उन्हें काम के लिए अपनी जेब से 5,000 रुपये से ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं।

एआईयूटीयूसी नेता कॉमरेड विश्वजीत हारोड़े ने कहा कि सरकार मंत्रियों, विधायकों और सांसदों को लाखों रुपये भत्ते के तौर पर देती है, लेकिन आम वर्करों को पैसे देने में आनाकानी करती है। महिला वर्करों ने मांग पूरी नहीं होने पर और जोरदार संघर्ष करने का संकल्प लिया।

यूनियन की प्रधान ऐश्वर्या राय, महासचिव रामेश्वरी राजपूत समेत कई नेताओं ने बातें रखीं।

हरियाणा के किसानों, मजदूरों और बिजली कर्मचारियों का महासम्मेलन आयोजित

जीन्द: महासम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कॉमरेडे हरिप्रकाश

जीन्द (हरियाणा) : किसानों, मजदूर-कर्मचारियों और आम लोगों पर किये जा रहे पूंजी के हमलों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा, केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों व कर्मचारियों की फेडरेशनों के संयुक्त मंच और बिजली कर्मचारियों व इंजीनियरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति (एनसीसीओईई) के आह्वान पर 15 जनवरी को यहां किसान-मजदूर महासम्मेलन आयोजित किया गया।

महासम्मेलन में मजदूर-विरोधी चार लेबर कोड, भारत के रूपांतरण हेतु परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन एवं संवर्धन ('शांति') कानून-2025, मनरेगा को खत्मकर विकसित भारत रोजगार एंड आजीविका (ग्रामीण) अधिनियम 2025, किसान-विरोधी मसौदा बीज विधेयक और जनविरोधी मसौदा बिजली (संशोधन) विधेयक 2025 को रद्द करने, बीमा क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई की नीति और विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 वापस लेने की मांग की गई। संगठनों ने प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगाने बंद करने और क्रॉस-सब्सिडी व सार्वजनीन सेवा दायित्व को बरकरार रखने, किसानों सहित सभी उपभोक्ताओं के बिजली अधिकार की रक्षा करने और बिजली दरें कम करने की भी मांग की।

महासम्मेलन ने चार लेबर कोडों के खिलाफ केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर 12 फरवरी की आम हड़ताल का समर्थन किया।

महासम्मेलन को अन्य वक्ताओं के अलावा एआईयूटीयूसी के राज्य सचिव कॉमरेड हरिप्रकाश, ऑल इण्डिया पावरमेन्स फेडेशन के उपाध्यक्ष कॉमरेड मेहर सिंह बांगड़ और एआईकेकेएमएस की ओर से कॉमरेड ईश्वर सिंह दहिया ने भी सम्बोधित किया।

महासम्मेलन में हजारों किसानों, मजदूरों, बिजली उपभोक्ताओं और बिजली कर्मचारियों ने भाग लिया।

एसकेएम के बैनर तले किसान सड़कों पर उतरे

सोनीपत (हरियाणा): सरकार की किसान-मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से पूरे भारत में सभी जिलों में प्रदर्शन करने के आह्वान पर इसके घटक किसान संगठनों ने 26 जनवरी को यहां महलाना चौक पर इकट्ठा होकर जोरदार नारे लगाते हुए छोटूराम चौक तक प्रदर्शन किया।

एसकेएम ने सरकार से एमएसपी की कानूनी गारंटी देने, बीज बिल वापस लेने, बिजली (संशोधन) बिल रद्द करने, स्मार्ट मीटर लगाना बंद करने, गरीब किसानों के कर्ज माफ करने और बारिश से हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि सरकार चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। इसकी वजह से लगातार महंगाई बढ़ रही है।

आज के इस विरोध प्रदर्शन में ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के अध्यक्ष हंसराज राणा, जयकरण दहिया, भारतीय किसान यूनियन टिकेत के नेता राज सिंह दलाल, राजकुमार राणा, ऑल इंडिया किसान सभा के नेता श्रद्धानंद सोलंकी, सिलक राम मलिक, किसान मजदूर पंचायत के वजीर सिंह, कॉमरेड हरिप्रकाश, ईश्वर सिंह दहिया, दलबीर सिंह, सुरेंद्र छीकारा, वेद प्रकाश, धर्मवीर सिंह, भारत, प्रताप सिंह आदि ने भाग लिया।

10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर चार काले श्रम कोड के खिलाफ

राज्य स्तरीय मजदूर कन्वेंशन संपन्न

12 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय आम हड़ताल सफल करने का लिया संकल्प

निजीकरण, ठेकाकरण, आउटसोर्स पर लगाम लगाने की उठायी मांग

पटना: श्रमिक सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड सूर्यकर जितेन्द्र

पटना (बिहार) : 25 जनवरी को आई एम ए हॉल, पटना में मजदूरों की संयुक्त कन्वेंशन आयोजित की गई। इस कन्वेंशन की अध्यक्षता संयुक्त अध्यक्ष मंडल ने की, जिसमें इंटक से नंदन मंडल, एटक से डीपी यादव, सीटू से गणेश शंकर सिंह, ऐक्टू से चंद्र शेखर कुमार तथा एआईयूटीयूसी से उमाशंकर वर्मा शामिल थे।

ऐक्टू के बिहार महासचिव आर एन ठाकुर द्वारा पेश किये गये कन्वेंशन के घोषणा पत्र पर विभिन्न केंद्रीय श्रमिक संगठनों के नेताओं ने अपनी-अपनी बातें रखीं। कन्वेंशन को संबोधित करते हुए मजदूर नेताओं ने कहा कि तमाम विरोधों के बावजूद केंद्र सरकार ने देशी-विदेशी उद्योगपतियों-पूंजीपतियों के हित में मजदूर-विरोधी चार श्रम संहिताओं (लेबर कोड) को दबंगई के साथ लागू कर दिया है। इनके खिलाफ मजदूर यूनियनों द्वारा निरंतर देशव्यापी आंदोलन के साथ-साथ हड़तालें भी की गईं, परंतु भाजपा -नीत मोदी सरकार ने सब अनसुना कर दिया।

दरअसल, ये चार श्रम संहिताएं बुनियादी रूप से मौजूदा अंधाधुंध निजीकरण और व्यापार-वाणिज्य की बदलती जरूरतों को पूरा करने के मकसद से लायी गई हैं। इनमें मजदूर वर्ग के हितों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। ये सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया में बाधाएं पैदा करेंगे। ये सब राजकीय पूंजी और निजी पूंजी के हित में 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' सुनिश्चित करने और मालिकों / प्रबंधकों द्वारा मजदूर वर्ग के बेरोकटोक शोषण का मार्ग प्रशस्त करने का एक नया हथियार है।

ये हमले होते देख मजदूर वर्ग चुपचाप नहीं बैठेगा। मजदूर लड़ेंगे, लड़कर जीतेंगे। हर जिले में व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए मजदूर कर्मचारियों को सड़क पर उतारने का काम करेंगे। आगामी 12 फरवरी 2026 को संपूर्ण बिहार में मजदूर-कर्मचारी सड़क पर उतरेंगे।

कन्वेंशन को संबोधित करने वालों में इंटक के बिहार महासचिव अखिलेश पांडे, एटक के सचिव कौशलेंद्र वर्मा, सीटू के बिहार महासचिव अनुपम कुमार, एआईयूटीयूसी के बिहार प्रदेश सचिव कॉमरेड सूर्यकर जितेंद्र तथा एक्टू नेत्री एवं एमएलसी शशि यादव शामिल थे।

अंत में अध्यक्ष मंडल की ओर से एटक के डीपी यादव ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

प्रतिरोध दिवस पर किसान संगठनों ने किया संयुक्त प्रदर्शन

तोशाम (हरियाणा): जनविरोधी बिजली (संशोधन) विधेयक-2025, स्मार्ट मीटर लगाने, मनरेगा को विबीजीरामजी अधिनियम-2025 के बहाने खत्म करने, मजदूर-विरोधी चार लेबर कोड, किसान-विरोधी बीज विधेयक-2025 और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी कंपनियों के हवाले करने वाले 'शांति' एक्ट के खिलाफ तथा इस इलाके से होकर गुजरने वाली हाई बोल्टेज लाइन के मुआवजे की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन, किसान सभा, ग्राम स्वराज किसान मोर्चा, रिटायर्ड कर्मचारी संगठन और रिटायर फौजी संगठन ने मिलकर 16 जनवरी को तोशाम सब-डिविजन कार्यालय पर आक्रोश प्रदर्शन किया।

किसान नेताओं ने कहा कि ये काले कानून किसानों की आजीविका, मजदूरों के अधिकार, खाद्य सुरक्षा, रोजगार गारंटी और राज्यों के संघीय अधिकारों पर गंभीर खतरा पैदा करते हैं।

किसान-मजदूरों ने शपथ ली कि जब तक सरकार किसान-मजदूरों के खिलाफ बनाये गये इन अन्यायपूर्ण कानूनों को वापस नहीं ले लेती, तब तक आंदोलन जारी रखेंगे।

पुलिस दमन के बावजूद आशा कर्मियों ने बहादुरी के साथ दिखाया संघर्ष का जज्बा

कोलकाता (प.बं.) : केंद्र और राज्य सरकारों से अपनी जायज मांगों को मनवाने के लिए एआईयूटीयूसी से संबद्ध आशा कार्यकर्ता यूनियन और पौर स्वास्थ्य कर्मी (कंट्रक्टच्यूअल) यूनियन के साझे बैनर तले 40,000 से ज्यादा जोशीली महिलाओं ने 21 जनवरी को शहर में विरोध प्रदर्शन करते हुए स्वास्थ्य भवन, राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर कूच किया। पक्के इरादे, नये जोश और संघर्ष के जज्बे के साथ वे सड़कों पर उतरीं। इनके आन्दोलन को दबाने के लिए पुलिस ने दमनात्मक कार्रवाई की, जिसके खिलाफ 22 जनवरी को विरोध दिवस मनाया गया और 28 जनवरी को सभी सब-डिवीजनों में प्रदर्शन आयोजित किये गये।

30 जनवरी को जानी-मानी हस्तियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीड़ित आशा कार्यकर्ताओं के जायज आंदोलन पर दमनात्मक पुलिसिया कार्रवाई के लिए राज्य सरकार की निंदा की। संघर्षरत आशा कार्यकर्ता जब तक मांगें पूरी नहीं हो जाती, तब तक अपना आंदोलन जारी रखने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। हम आशा कार्यकर्ताओं के संघर्ष को सलाम करते हैं।

PRGI Regn. No. 43022

जम्मू में मेडिकल कॉलेज बंद : नफरत की राजनीति के भयावह नतीजे

आसिफ की तमन्ना थी कि वह मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेगा, हॉस्टल में साथियों के साथ रहकर पढ़ाई करेगा, दूर-दराज के आम लोगों और पड़ोसियों के इलाज में मदद करेगा, माता-पिता के चेहरों पर मुस्कान लायेगा, लेकिन हिन्दुत्ववादी संगठनों की अड़ंगेबाजी की वजह से उसकी तमन्ना धरी की धरी रह गयी। सिर्फ उसकी ही नहीं, बल्कि कई मुसलमान और यहां तक कि हिन्दू छात्रों की तमन्ना भी अधूरी रह गयी। मंजूरी मिलने के सिर्फ चार महीने के अंदर एनएमसी की आड़ में केन्द्र की भाजपा सरकार ने जम्मू के कटरा में वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को पूरी तरह से गैर-कानूनी करार देते हुए अचानक बंद कर दिया। यह घटना राज्य और देश के इतिहास में एक शर्मनाक घटना की मिसाल बन गयी है।

आर्थिक रूप से पिछड़े और दूर-दराज के इलाकों के लोगों के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर कितने जरूरी होते हैं, यह तो सब समझते हैं। लेकिन कटरा में श्री माता वैष्णो देवी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज को बंद करने का फैसला सुनाते समय सरकार ने जन स्वास्थ्य के बारे में जरा भी नहीं सोचा। एनएमसी ने कहा कि कॉलेज में शिक्षकों की कमी है, लाइब्रेरी नहीं है और क्लासरूम भी सही-सलामत नहीं हैं। क्या सरकार को कॉलेज को मंजूरी देते समय इन सब बातों की जानकारी नहीं थी? अगर थी, तो उन कमियों को पूरा किये बिना कॉलेज को किस आधार पर मंजूरी दी गयी? इसलिए यह समझने में दिक्कत नहीं है कि ऐसा कहना दरअसल एक बहाना है।

दरअसल, कॉलेज बंद होने के पीछे मुसलमानों से नफरत है। भाजपा से जुड़े हिन्दुत्ववादी संगठनों ने कॉलेज को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने की मांग पर प्रदर्शन किया। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक ज्ञापन सौंपा। क्योंकि उनका दावा है कि कॉलेज वैष्णो देवी मंदिर के तीर्थयात्रियों के दान से बना था। इसलिए मुसलमान या दूसरे धर्म के छात्र उस कॉलेज में पढ़ नहीं पायेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि दाखिला किस आधार पर लिया जायेगा, धर्म के आधार पर या मेधा के आधार पर? इसके अलावा, सरकार और स्थानीय प्रशासन को तो पता ही था कि वहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। इसलिए ऑल इंडिया नीट की परीक्षा में मेधा के आधार पर ही पहले साल में 50 सीटों पर 42 मुसलमान छात्रों का दाखिला हुआ। सब कुछ कानून के अनुसार ही हुआ। बावजूद इसके, बिना किसी सूचना के कॉलेज को पूरी तरह से गैर-कानूनी तरीके से बंद कर दिया गया।

(शेष पृष्ठ 8 पर)

जम्मू मैडिकल कॉलेज बंद करने का फैसला सांप्रदायिक सोच से प्रेरितः एआईडीएसओ

जम्मू के 'श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस' की मान्यता रद्द करने के नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) के फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए छात्र संगठन एआईडीएसओ के महासचिव कॉमरेड शिवाशीष प्रहराज ने 9 जनवरी को जारी एक प्रेस बयान में कहा,

"हमें लगता है कि यह सांप्रदायिक सोच से प्रेरित कदम है, जिसमें एनएमसी को एक औजार की तरह इस्तेमाल किया गया है। कई हिंदू कट्टरपंथी गुटों के कॉलेज में दाखिला लेने वाले मुस्लिम छात्रों के अनुपात के खिलाफ विरोध करने के बाद एनएमसी ने न्यूनतम स्तर की कमी का हवाला देते हुए यह कदम उठाया। यह याद रखना जरूरी है कि दाखिले की प्रक्रिया कोई रैंडम सिलेक्शन नहीं थी, बल्कि एनईईटी की मेरिट लिस्ट के आधार पर थी। भाजपा ने भी दाखिले की इस प्रक्रिया को रद्द करने की मांग करते हुए केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक ज्ञापन दिया था। जबकि सरकार की प्राथमिकता और नए मेडिकल कॉलेज खोलना और न्यूनतम स्तर बनाये रखने के लिए कड़े कदम उठाना होना चाहिए, एमबीबीएस कोर्स शुरू करने की इजाजत देने के एक साल के अंदर कॉलेज को बंद करने से देश के हर सोचने वाले इंसान के मन में सरकार के इरादों पर शक पैदा हो गया है।

एआईडीएसओ इस मेडिकल कॉलेज को बंद करने के फैसले का कड़ा विरोध करता है और देश के आम लोगों, खासकर छात्र समुदाय से अपील करता है कि वे सत्ताधारी पार्टी के इस छात्र-विरोधी और शिक्षा-विरोधी सांप्रदायिक कदम के खिलाफ आंदोलन में आगे आएं।"

एआईयूटीयूसी ने अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ किया प्रदर्शन

डब्ल्यूएफटीयू ने इंटरनेशनल एक्शन डे के रूप में मनाया 22 जनवरी

पटना

चेन्नई

पटना (बिहार) : 22 जनवरी को ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर (एआईयूटीयूसी) ने वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस (डब्ल्यूएफटीयू) के आह्वान पर पटना के बुद्ध स्मृति पार्क में अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा वेनेजुएला पर हमले का विरोध किया।

विरोध प्रदर्शन में लोग 'अमेरिकी साम्राज्यवाद वेनेजुएला से तुरंत दूर हटो', 'वेनेजुएला के अपहृत राष्ट्रपति मादुरो एवं सीलिया फ्लोर्स को रिहा करो', 'युद्ध-विरोधी जुझारू शांति आंदोलन तेज करो', 'जनवाद पसंद, शांति पसंद लोग वेनेजुएला के साथ खड़े हों', 'युद्ध रोको', 'पूंजीवाद -साम्राज्यवाद मुर्दाबाद' आदि नारे लगा रहे थे।

विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए एआईयूटीयूसी के बिहार राज्य कमेटी के सचिव कॉमरेड सूर्यकर जितेंद्र ने कहा कि जंगखोर अमेरिकी साम्राज्यवादियों द्वारा वेनेजुएला पर किये गए बेहद घृणित सैन्य हमले की जिन भी शब्दों में कड़ी निन्दा की जाए, वे कम हैं। यह हमला केवल वेनेजुएला पर ही नहीं, बल्कि पूरे लैटिन अमेरिका पर किया गया है, जिसका उद्देश्य वहां के सभी देशों को बंदूक की नोक पर अधीन करना है। वास्तव में अमेरिका द्वारा झूठा आरोप लगाकर वेनेजुएला पर हमला किया गया है। वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया को गिरफ्तार किया गया है। जंगखोर अमेरिका वेनेजुएला की राजधानी पर बमबारी कर रहा है। इस बर्बर हमले में लोग मारे जा रहे। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी सरेआम उल्लंघन कर रहा है। ट्रंप अपने आपको शांति का दूत कहते हैं, लेकिन वे दुनिया में अशांति फैला रहे हैं। हालात का तकाजा है कि सभी साम्राज्यवाद-विरोधी, युद्ध-विरोधी और शांतिप्रिय लोग इस जघन्य हमले के खिलाफ तुरंत विरोध प्रदर्शन करें, पीड़ित वेनेजुएलावासियों के साथ खड़े हों और साम्राज्यवादी लूटेरों को लैटिन अमेरिका से पीछे हटने के लिए मजबूर करें।

वक्ताओं में एसयूसीआई (सी) राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड राजकुमार चौधरी और एआईडीवाईओ के राज्य सचिव कॉमरेड विकास कुमार प्रमुख थे। अध्यक्षता एआईयूटीयूसी, बिहार राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड अनामिका कुमारी ने की।

चेन्नई (तमिलनाडु): डब्ल्यूएफटीयू के आह्वान पर भारत के इसके सहयोगियों ने यहां अमेरिकी साम्राज्यवाद के विरोध में प्रदर्शन किया और मादुरो को रिहा करने की मांग की। इसमें एआईयूटीयूसी, सीटू, एटक, यूटीयूसी व एआईसीसीटीयू ने हिस्सा लिया।

कॉमरेड चक्रवर्ती विश्वकर्मा की याद में श्रद्धांजलि सभा आयोजित

पट्टी, प्रतापगढ़, उ.प्र।

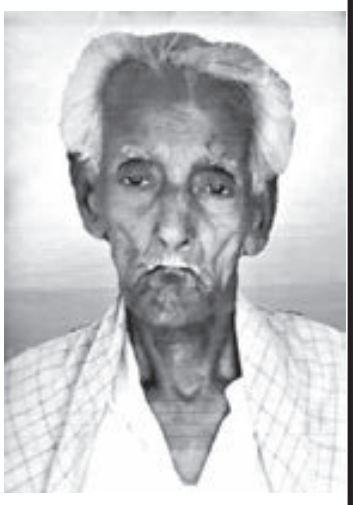

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एसयूसीआई (सी) के दाउदपुर लोकल कमेटी सदस्य कॉमरेड चक्रवर्ती विश्वकर्मा, निवासी दाउदपुर, प्रतापगढ़ का निधन विगत 28 दिसम्बर 2025 को सुबह लगभग 10:30 बजे हो गया था। वे 88 वर्ष के थे। पेशे से वे एक अच्छे अध्यापक थे। 10 जनवरी 2026 को उनकी याद में दाउदपुर, पट्टी, प्रतापगढ़ में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गयी, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा क्षेत्र के सैकड़ों लोग मौजूद रहे।

सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि कॉमरेड चक्रवर्ती विश्वकर्मा सबसे पहले 1971 में सीपीआई से जुड़े। उस समय जमींदारी के खिलाफ और मजदूरी बढ़ाने को लेकर आंदोलन चल रहा था। उसी समय महराजगंज क्षेत्र के सराय पड़री के कॉमरेड कुंवर सिंह से संपर्क हुआ। उसके बाद एसयूसीआई (सी) के भूतपूर्व राज्य सचिव दिवंगत कॉमरेड वी.एन सिंह से उनकी मुलाकात हुई, जिनके माध्यम से ही वे इस युग के विशिष्ट मार्क्सवादी दार्शनिक, सर्वहारा वर्ग के महान नेता, शिक्षक व पथ-प्रदर्शक और एसयूसीआई (सी) के संस्थापक महासचिव कॉमरेड शिवदास घोष की शिक्षाओं से प्रेरित हुए। इस तरह वे शिक्षक की नौकरी करते हुए सक्रिय रूप से पार्टी का काम करने में जुट गये। 1976 में सरकार द्वारा चलाए गये जबरन नसबंदी अभियान के खिलाफ गांव-गांव घूमकर कॉमरेड कुंवर सिंह एवं कॉमरेड चक्रवर्ती विश्वकर्मा ने संगठन तैयार किया। इसी बीच 21 दिसंबर 1976 को बेसार गांव में पुलिस बर्बरता एवं गोलीकांड हुआ। इस गोलीकांड में बेसार गांव के जोखू राम पटेल शहीद हुए थे और दर्जनों लोग घायल हुए थे। तभी से इस क्षेत्र में पार्टी की पहचान बनी।

कॉमरेड चक्रवर्ती विश्वकर्मा के संघर्ष को देखते हुए 1988 में पार्टी ने उन्हें जिला कमेटी सदस्य बनाया। जब 2002 में वे शिक्षक पद से सेवानिवृत्त हुए, तो उसी समय से वे बहुत अस्वस्थ हो गए और घर पर रहने लगे। लेकिन वे हमेशा पार्टी के लिए चिंतित रहते। उन्होंने अपने इकलौते बेटे दिवंगत कॉमरेड पुष्पेन्द्र विश्वकर्मा को नौकरी न करके छात्र संगठन एआईडीएसओ में काम करने का सुझाव दिया, जिसके अनुरूप चलते हुए उनका बेटा पुष्पेन्द्र विश्वकर्मा भी एक अच्छा सक्रिय संगठक और एआईडीएसओ का उत्तर प्रदेश राज्य संयोजक बना। बाद में कॉमरेड पुष्पेन्द्र विश्वकर्मा एसयूसीआई (सी) के उत्तर प्रदेश राज्य सचिव बने। लेकिन अपने इकलौते बेटे कॉमरेड पुष्पेन्द्र की असमय मौत के बाद भी कॉमरेड चक्रवर्ती विचलित नहीं हुए। वे अपने पोते-पोतियों को भी एआईडीएसओ से जुड़कर संगठन का काम करने के लिए आजीवन प्रेरित करते रहे। वे स्वयं एसयूसीआई (सी) पार्टी की दाउदपुर लोकल कमेटी सदस्य के रूप में कार्यरत रहे। पार्टी कॉमरेडों ने अपने दिवंगत कॉमरेड के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक की इस घड़ी में कॉमरेड के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की।

श्रद्धांजलि सभा की शुरुआत दिवंगत कॉमरेड चक्रवर्ती विश्वकर्मा की फोटो पर माल्यार्पण करके की गई। इस अवसर पर एसयूसीआई (सी) के केन्द्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड स्वपन चटर्जी की गैर मौजूदगी में उनकी ओर से पार्टी के पूर्वी उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड दिलीप कुमार खरवार द्वारा माल्यार्पण किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉमरेड रामशरण विश्वकर्मा ने की और संचालन कॉमरेड विजयानंद तिवारी ने किया। सभा को पार्टी के पूर्वी उत्तर प्रदेश राज्य कार्यालय सचिव कॉमरेड जगन्नाथ वर्मा, प्रतापगढ़ जिला सचिव कॉमरेड बेचन अली के अलावा कॉमरेड जयप्रकाश मौर्य, कॉमरेड मिथिलेश कुमार मौर्य, कॉमरेड प्रमोद कुमार शुक्ल, कॉमरेड मनोज चौरसिया व अन्यों ने सम्बोधित किया।

अंत में दो मिनट का मौन रखकर और कॉमरेड शिवदास घोष पर रचित गीत गाकर कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

कॉमरेड चक्रवर्ती प्रसाद विश्वकर्मा लाल सलाम

एआईकेकेएमएस के राज्य सचिव कॉमरेड भगवान रेड्डी की रिहाई का स्वागत

106 दिन के विजयपुर जनसंघर्ष की जीत का अभिनंदन

विजयपुर कर्नाटक): ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन (एआईकेकेएमएस) ने अपने कर्नाटक राज्य सचिव कॉमरेड भगवान रेड्डी और विजयपुर संघर्ष समिति के पांच सदस्यों की रिहाई का स्वागत किया, जिन्हें विजयपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निजीकरण के खिलाफ जोरदार जन आंदोलन का नेतृत्व करने पर गिरफ्तार किया गया था।

संघर्ष समिति और विजयपुर के लोगों ने सरकारी अस्पताल के पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल को लागू करने का कड़ा विरोध किया, जिसका मकसद सरकारी अस्पताल का निजीकरण करना और शहर के बीचों-बीच स्थित लगभग 150 एकड़ की कीमती सरकारी जमीन को निजी कॉर्पोरेट हितों को सौंपना था।

लगातार 106 दिन चले जोरदार संघर्ष के बाद सरकार को जनता के दबाव के आगे झुकना पड़ा। विजयपुर में हुई एक जनसभा में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घोषणा की कि सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निजीकरण नहीं किया जाएगा।

एआईकेकेएमएस ने इसे जन आंदोलन की एक ऐतिहासिक जीत और एक स्पष्ट संदेश माना कि एकजुट सतत संघर्ष से जनविरोधी और कॉर्पोरेट परस्त नीतियों को रद्द करा सकते हैं।

एआईकेकेएमएस ने आम लोगों, खासकर किसान-खेत मजदूरों से निजीकरण का विरोध करने और केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा अपनायी जा रही सभी जनविरोधी नीतियों को वापस कराने के लिए एकजुट होने और जन आंदोलन छेड़ने का आह्वान किया।

मैकाले....

(पृष्ठ 3 का शेष)

विदेशी विमान में चढ़ते हैं। उनकी पार्टी के ज्यादातर नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। 'स्वदेशी' युद्ध विमान 'तेजस' सरकारी कंपनी 'एचएएल' ने अमेरिकी इंजन से बनाया है। स्वदेशी 'ब्रह्मोस' मिसाइल रूसी इंजन से बनी है। दवाइयों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सभी आयातित वस्तुओं से तैयार होते हैं। फिर भी वे कहते रहते हैं कि 'विदेश से आयातित शासन प्रणाली को वे स्वदेशी मॉडल में बदल देंगे!' क्या वे विदेशी अनुकरण मानकर संसदीय व्यवस्था को त्यागकर राजशाही शासन में लौटना चाहेंगे?

आरएसएस सेवक के रूप में मोदीजी का असली स्वदेशीपन क्या है? उनकी शिक्षा नीति में दिख रहा है कि वे शिक्षा को महंगे उत्पाद में बदलना चाहते हैं। इससे देश के अधिकतर गरीबों को वैज्ञानिक और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलना असंभव हो जाएगा। यह एक पहलू है, लेकिन यही पूरा नहीं। राम मंदिर में खड़े होकर मैकॉले का नाम लेने का संकेत है—जो काम उन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़कर सामाजिक-राजनीतिक क्षेत्र में किया, 2014 से गुजरात में शिक्षा क्षेत्र में शुरू किया—उसी काम को वे आगे बढ़ाने पर अमादा हैं। काम यह है कि देश में धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक वैज्ञानिक चिंतन के रास्ते को पूरी तरह बंद करना। ध्यान देना चाहिए कि 'धर्मनिरपेक्षता' की अवधारणा पूरे विश्व में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की नींव मानी जाती है, फिर भी भाजपा इसे 'विदेशी विचार' कहकर प्रचार कर रही है। क्योंकि उनका लक्ष्य है 'हिंदू भारत', जहां मुस्लिम सहित अन्य धर्मावलंबियों को दोयम श्रेणी का नागरिक बनकर रहना होगा। राम मंदिर में खड़े होकर मैकॉले का नाम लेकर नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत उसी रास्ते को खोलना चाहते हैं। इसी रास्ते से वे राष्ट्रीयता के नाम पर उग्र नकली देशप्रेम आयात करना चाहते हैं। भारतीय राष्ट्रीयता तो ब्रिटिश-विरोधी आजादी आन्दोलन के रास्ते से ही बनी है। लेकिन आरएसएस उससे दूर रहा। एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले सभी धर्म, जाति, वर्ग के लोगों ने जब मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तब उसी क्रम में भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ। आरएसएस का दर्शन इस राष्ट्रीयता का घोर विरोधी है। वे चाहते हैं हिंदू धर्म आधारित 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद'। आरएसएस ने ब्रिटिश-विरोधी आजादी आंदोलन का विरोध किया, मुस्लिम-विरोधी आंदोलन चाहा—उसका कारण यही था। उनके नेता सावरकर कहते थे कि कोई राष्ट्र केवल बहुसंख्यक समुदाय से ही बन सकता है। इसलिए वे जर्मनी में यहूदियों के संहार के समर्थक थे।

संकटग्रस्त एकाधिकारी पूंजीवाद ने ही फासीवाद को पैदा किया है और आज भारत में आरएसएस-भाजपा उसका सबसे शक्तिशाली वाहक हैं। मानव समाज की प्रगति का मार्ग रोकने के लिए ही यह फासीवाद पैदा हुआ है। संकटग्रस्त पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंककर शोषणमुक्त समाजवादी व्यवस्था कायम होना और उसके लिए समाज में जो क्रांतिकारी चिंतन पैदा होना अनिवार्य है, उसे रोकने के लिए ही पूंजीपति वर्ग फासीवाद लाता है। इसके लिए वह उन्नत वैज्ञानिक चिंतन, राज्य और समाज में धर्मनिरपेक्षता का आदर्शबोध, लोकतांत्रिक मूल्यों का अभ्यास—इन सबको रोकना चाहता है। फासीवादी ताकतें तर्क-वितर्क को मारना चाहती हैं और अंधता को बढ़ाना चाहती हैं। महान मार्क्सवादी चिंतक कॉमरेड शिवदास घोष ने गहरी चिंता व्यक्त की थी कि अगर फासीवाद का उभार हो गया, तो देश में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बचेगी, क्योंकि फासीवाद इन्सान बनने की प्रक्रिया को अवरुद्ध कर देता है। जिस चिंतन से इन्सान का विकास, प्रगति और समाज की सर्वांगीण उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है—फासीवाद उस पर प्रहार करता है। राममोहन, विद्यासागर, रवींद्रनाथ, शरतचंद्र, सुभाषचंद्र, भगत सिंह आदि के रास्ते पर अगर देश के लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसके नतीजतन वह उन्हें वैज्ञानिक समाजवाद यानी मार्क्सवाद-लेनिनवाद के दिखाये मार्ग पर ले जाएगा। इस रास्ते पर चलने वाले लोग ही फासीवाद का हर तरह से मुकाबला कर सकते हैं। आरएसएस-भाजपा को यही डर है। लेकिन नरेंद्र मोदी जानते हैं कि अगर वे अभी इन सभी मनीषियों के नाम लेकर हमला करेंगे, तो उसका परिणाम उल्टा होगा। इसलिए उन्होंने चुना है मैकॉले को। मानो मैकॉले ही 'आधुनिक' शिक्षा के जनक हों! असल में 'विदेशी' 'विदेशी' का नारा लगाकर पहले धर्मनिरपेक्षता पर हमला, फिर लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला, वैज्ञानिक चिंतन पर हमला और अंततः आज के युग की सर्वश्रेष्ठ विचारधारा मार्क्सवाद-लेनिनवाद जैसे विश्वव्यापी विज्ञान और दर्शन को विदेशी बताकर उस पर हमला करना ही उनका मुख्य मकसद है।

बिजली (संशोधन) विधेयक..

(पृष्ठ 1 का शेष)

वित्तीय संकट का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा, एक ही इलाके में कई निजी कंपनियों को वितरण कारोबार चलाने की इजाजत देने से असल में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाना जरूरी हो जाएगा, जो उपभोक्ताओं को लूटने के एक जरिये के सिवा और कुछ नहीं है।

5) उपभोक्ता एसोसिएशनों ने इस प्रस्ताव को खारिज करने की गुजारिश की है कि अगर वितरण कंपनियां हर साल तय समय के अंदर अपना आवेदन जमा नहीं करती हैं, तो बिजली नियामक आयोग दरें (खुद से) तय करे। उन्होंने यह भी प्रस्ताव दिया है कि आयोग को उपभोक्ताओं के संगठनों से सलाह किये बिना दरें तय नहीं करनी चाहिए।

6) यह संशोधन बिल लागत-आधारित टैरिफ का प्रस्ताव देता है। यह प्रस्ताव आम उपभोक्ताओं और कृषि बिजली उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ है, क्योंकि ये उपभोक्ता कमर्शियल कामों के लिए बिजली का इस्तेमाल नहीं करते हैं।

7) इस तर्क के बारे में कि सरकारी बिजली वितरण कंपनियां भारी घाटे में चल रही हैं, उन्होंने वितरण व्यवस्था के निजीकरण के खिलाफ कहा है कि 'बिजली कानून 2003' पहले से ही सभी बिजली उत्पादन कंपनियों, ट्रांसमिशन कंपनियों और वितरण कंपनियों को अपनी निवेशित पूंजी पर कम से कम 16 प्रतिशत (इक्विची पर उचित रिटर्न) मुनाफा जोड़कर दरें (टैरिफ) तय करने का अधिकार देता है। उन्होंने ओडिशा का उदाहरण दिया, जहां पूरी तरह निजीकरण के बाद ग्राहक सेवा में बड़ी लापरवाही के कारण राज्य सरकार को कई निजी कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने पड़े।

8) संविधान कहता है कि बिजली केंद्र और राज्य सरकारों का समवर्ती विषय है। उपभोक्ता एसोसिएशनों ने इस संशोधन बिल में बिजली व्यवस्था को पूरी तरह केंद्रीकृत करने की कोशिश का कड़ा विरोध किया है।

9) उपभोक्ता एसोसिएशनों ने मांग की है कि बिजली से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले सबसे बड़े हितधारक यानी बिजली उपभोक्ता संगठनों से सलाह ली जाए।

10) इस संशोधन बिल को राय के लिए बिजली पर संसदीय समिति के पास भेजा गया है। उनकी मांग है कि समिति की राय जनता की जानकारी के लिए तुरंत प्रकाशित की जाए।

अमरकंटक विश्वविद्यालय में छात्र के साथ हुई नस्लीय हिंसा की

एआईडीएसओ ने की निंदा

दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की

भोपाल (मध्य प्रदेश): मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के छात्रावास में असम के 22 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट छात्र के साथ कथित तौर पर नस्लीय भेदभाव के चलते हुई मारपीट की घटना अत्यंत निंदनीय, अमानवीय और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। इस घटना की निंदा करते हुए मध्य प्रदेश राज्य काउंसिल सचिव नारायण चंदेल ने 19 जनवरी को जारी प्रेस बयान में कहा कि यह घटना न केवल एक छात्र पर हमला है, बल्कि देश की एकता पर सीधा प्रहार है।

यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की नस्लीय नफरत के कारण निर्मम हत्या कर दी गई। एक के बाद एक सामने आ रही इन घटनाओं से साफ जाहिर है कि देश के विभिन्न हिस्सों में अध्ययन कर रहे पूर्वोत्तर राज्यों के छात्र आज भी नस्लीय भेदभाव, अपमान और हिंसा के शिकार हो रहे हैं। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है।

विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान ज्ञान, तर्क, वैज्ञानिक सोच और मानवीय मूल्यों के केंद्र होते हैं। इन्हें सामाजिक समरसता और भाईचारे का उदाहरण पेश करना चाहिए, लेकिन जब इन्हीं परिसरों में नफरत, संकीर्ण सोच और हिंसा को जगह मिलती है, तो यह शिक्षा व्यवस्था की गंभीर विफलता को दर्शाता है। ऐसी घटनाएं यह सवाल खड़ा करती हैं कि क्या हमारे शैक्षणिक संस्थान छात्रों को सुरक्षित वातावरण देने में विफल हो रहे हैं? शासक वर्ग इन घटनाओं को रोकने की बजाय इन्हें बढ़ावा देने का काम कर रहा है। ऐसी ही घटना बैतूल जिले में हुई है, जिसमें एक व्यक्ति के प्रयास से निर्माणाधीन स्कूल को सरकार ने धार्मिक रंग देकर तोड़ दिया। आजादी के 78 वर्षों बाद भी देश में धार्मिक, जातीय और नस्लीय भेदभाव जारी है, जिसे सत्ता का संरक्षण मिल रहा है।

एआईडीएसओ यह दोहराता है कि भारत विविधताओं का देश है, जहां अलग-अलग भाषाएं, संस्कृतियां और क्षेत्रों के लोग मिल-जुलकर रहते हैं। इसी विविधता में हमारी ताकत है। किसी भी छात्र के साथ उसकी नस्ल, भाषा या क्षेत्र, धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव करना देश की एकता को कमजोर करने वाला कृत्य है, जिसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम मांग करते हैं कि पूर्वोत्तर और अन्य राज्यों से आने वाले छात्रों की सुरक्षा के लिए प्रभावी तंत्र और शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत किया जाए। उक्त छात्र के साथ मारपीट करने वाले दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

एआईडीएसओ छात्रों, शिक्षकों और लोकतांत्रिक चेतना रखने वाले सभी नागरिकों से अपील करता है कि वे नस्लीय भेदभाव और हिंसा के खिलाफ एकजुट होकर आवाज बुलंद करें और इंसानियत, समानता व भाईचारे पर आधारित समाज बनाने में अपनी भूमिका निभायें।

'पंजाब केसरी' पर पंजाब सरकार की ज्यादतियों का

एसयूसीआई (सी) ने किया कड़ा विरोध

'पंजाब केसरी' लुधियाना के संपादक और कर्मियों पर झूठे मुकदमे बनाने की कड़ी निंदा करते हुए एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के हरियाणा राज्य सचिव कॉमरेड राजेंद्र सिंह एडवोकेट ने 25 जनवरी को जारी प्रेस बयान में कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका निभाने वाले प्रेस का कर्तव्य केवल समाचार प्रकाशित करना ही नहीं है, बल्कि सत्ता से सवाल पूछना और जनता की आवाज बनना है। सत्ता की आलोचना करना, जनता के बीच सरकार की गलत नीतियों को उजागर करना और जनहित के मुद्दों को सामने लाना ही पत्रकारिता का सच्चा कर्तव्य है। जनविरोधी नीतियों को जनता पर थोपने वाली पंजाब सरकार को यह सब हजम नहीं हो रहा है। इसलिए यह अलोकतांत्रिक कार्रवाई की गयी है, जो प्रेस की स्वतंत्रता के खिलाफ है।

एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) सभी प्रबुद्ध नागरिकों, प्रेस प्रेमियों और जनवाद पसंद नागरिकों से अपील करती है कि वे पंजाब सरकार के इस तानाशाही कदम के खिलाफ आवाज बुलंद करें।

PRGI Regn. No. 43022

बजट भाषण 2026 केवल अपनी बड़ाई का पुलिंदा, जनता की बदहाली का कोई जिक्र नहीं

वार्षिक बजट भाषण 2026 पर अपनी त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए एसयूसीआई (सी) के महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष ने 1 फरवरी को जारी एक बयान में कहा :

"जैसा कि अपेक्षित था, आज पेश किये गये बजट 2026 में देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति का कोई प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि यह संदेहास्पद तरीके से संकलित किये गए फर्जी आंकड़ों से भरा हुआ भाजपा सरकार का एक 'स्व-प्रशंसा पत्र' मात्र है। बजट में न तो स्पष्ट क्षेत्र-वार विशिष्ट आवंटन का उल्लेख किया गया है और न ही पहले घोषित परियोजनाओं या कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट या स्थिति के बारे में कुछ कहा गया है।

बजट भाषण को अकादमिक शब्दावली के अत्यधिक प्रयोग से जितना संभव हो सके उतना जटिल बना दिया गया है। यह स्पष्ट रूप से बड़े व्यापारिक घरानों और कर चोरों को अधिक से अधिक छूट और सहूलियत प्रदान करने का संकेत देता है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का दावा पूरी तरह से गलत बयानी है, खासकर जब इसे गलत मानकों और अनुचित विश्लेषण पद्धति के संदर्भ में देखा जाए।

बजट में बढ़ती मुद्रास्फीति, गिरते रुपये, बढ़ती बेरोजगारी, कारखानाबंदी, नौकरियों में कटौती, गरीब किसानों की गिरती आय और कृषि क्षेत्र के तेजी से हो रहे कॉर्पोरेटीकरण के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है, जबकि ये मुद्दे जनजीवन में तबाही मचा रहे हैं। नागरिकों के 'ईज ऑफ लिविंग' (जीवन की सुगमता) की चिंता पर 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (व्यापार की सुगमता) का वर्चस्व साफ नजर आया।

हम वार्षिक बजट को बुनियादी आर्थिक आंकड़ों और जनजीवन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों से रहित एक उपदेशात्मक दस्तावेज में तब्दील करने के इस प्रहसन पर अपना कड़ा आक्रोश व्यक्त करते हैं। इसमें लगातार कंगाल और संकटग्रस्त होते भारतीयों को राहत देने की दिशा में किसी भी ठोस कदम की घोषणा नहीं की गई है। हम इस बजट को एकदम सिरे से खारिज करते हैं।"

मजदूरों व ट्रेड यूनियनों पर देश में औद्योगिक विकास को बाधित करने के लगाये गए मुख्य न्यायाधीश के गैर-जिम्मेदाराना आरोप की एआईयूटीयूसी ने की कड़ी निंदा

नई दिल्ली : भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई इस टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कि ट्रेड यूनियनें देश में औद्योगिक विकास में बाधा डालने के लिए जिम्मेदार हैं, एआईयूटीयूसी के महासचिव कॉमरेड शंकर दासगुप्ता ने 30 जनवरी, 2026 को जारी प्रेस बयान में कहा :

"ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर (एआईयूटीयूसी) की अखिल भारतीय कमेटी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा देश में औद्योगिक विकास को बाधित करने के लिए श्रमिकों और ट्रेड यूनियनों पर लगाये गए गैर-जिम्मेदाराना आरोप की कड़ी निंदा करती है।

मुख्य न्यायाधीश की यह टिप्पणी 29 जनवरी 2026 को एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान आई थी। यह टिप्पणी स्पष्ट रूप से सरकार के उस रवैये से मेल खाती है, जो बड़े-बड़े एकाधिकारी पूंजीपति घरानों के इशारे पर काम कर रही है; मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी के लिए यह उपयुक्त नहीं है। यह टिप्पणी हमारे जैसे पूंजीवादी राज्य में न्यायपालिका के मालिक परस्त चरित्र को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। मजदूर वर्ग को इस बारे में जागरूक होने की जरूरत है ताकि वह हमारे देश की सत्ता में बैठे पूंजीपति वर्ग की ताबेदार सरकार के खिलाफ जोरदार एकजुट आंदोलन खड़ा कर सके।

मुख्य न्यायाधीश की यह टिप्पणी केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित तथ्यों से भी मेल नहीं खाती है। भारत सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 5 वर्षों में ट्रेड यूनियनों के कारण औद्योगिक विवादों की औसत संख्या 100 से काफी कम है, जबकि इसी अवधि में मालिकों के कारण औद्योगिक तालाबंदी की संख्या 40,000 से कहीं अधिक है।

मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने की कोई जरूरत नहीं है, जबकि कुछ राज्य इसे पहले ही तय कर चुके हैं और यह एक न्यायसंगत मुद्दा है, जिसे केंद्र सरकार वर्षों से नकारती आ रही है। मुख्य न्यायाधीश का यह बयान गरीब घरेलू कामगारों का घोर अपमान है।

एआईयूटीयूसी सहित 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों वेव मंच ने मजदूर-विरोधी, जनविरोधी और एकाधिकारी पूंजीपति परस्त 4 काले श्रम संहिताओं को रद्द करने और उनकी जगह 29 श्रम कानूनों को बहाल करने की मांग को लेकर आगामी 12 फरवरी को देशव्यापी आम हड़ताल का आह्वान किया है। मुख्य न्यायाधीश की यह टिप्पणी स्पष्ट रूप से केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा बुलाई गई न्यायोचित हड़ताल के प्रति केंद्र सरकार के विरोध का समर्थन करती है।

मुख्य न्यायाधीश की मजदूर-विरोधी, ट्रेड यूनियन-विरोधी, सरकार परस्त और मालिक परस्त टिप्पणी को खारिज करते हुए हम देश के मेहनतकशों और तमाम आम जनता से 12 फरवरी को होने जा रही देशव्यापी आम हड़ताल को मुकम्मल सफल बनाने के लिए अपनी तैयारियों को तेज करने का आह्वान करते हैं।

जनसंसद...

(पृष्ठ 1 का शेष)

इससे पहले, ऑल इण्डिया सेव एजुकेशन कमेटी (एआईएसईसी)द्वारा तैयार की गई जन शिक्षा नीति के बारे में महासचिव प्रो. तरुण कांति नस्कर ने शुरुआती बातें कहीं। उन्होंने कहा कि जब एनईपी-2020 में शिक्षा-विरोधी तत्वों के खिलाफ आवाज उठायी गई, तो यह सवाल उठा: हमें एक वैकल्पिक मॉडल क्यों नहीं बनाना चाहिए? इसी के तहत देशभर के कई शिक्षाविदों के सहयोग से शिक्षा नीति का एक मसौदा तैयार किया गया और मई 2025 में सार्वजनिक चर्चा-बहस के लिए जारी किया गया। इस ड्राफ्ट जन शिक्षा नीति (पीईपी) की लाखों प्रतियां सभी क्षेत्रीय भाषाओं में छापी गईं और लोगों के बीच बांटी गईं। इस पर पूरे भारत में सभी राज्यों में चर्चाएं हुईं। हजारों सुझाव मिले हैं। इन पर जन संसद में चर्चा की जाएगी ताकि नीति को अंतिम रूप दिया जा सके। आखिर में, इस नीति को लागू करने के लिए 'बेंगलुरु घोषणा' पेश की जाएगी।

कार्यक्रम की अध्यक्षता ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी (एआईएसईसी) के अध्यक्ष प्रकाश एन. शाह ने की। हम्पी यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर प्रो. ए. मूरिगेप्पा ने मेहमानों और प्रतिभागियों का स्वागत किया।

जन संसद में प्रो. अरुण कुमार, प्रो. आदित्य मुखर्जी, डॉ. निरंजनाराध्या वी.पी., प्रो. ए.एच. राजसाब, डॉ. फ्रांसिस असीसी अल्मेडा, प्रो. जवाहर नेसन, डॉ. महाबलेश्वर राव, डॉ. ए.आर. वासावी, डॉ. शिंटी एंटनी, प्रो. अल्लमाप्रभु बेट्टादुर और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 1,000 प्रतिनिधियों ने उत्साह के साथ भाग लिया।

उद्घाटन सत्र के बाद शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर अलग-अलग थीमेटिक सत्र आयोजित किये गए। जन शिक्षा नीति के अंतिम ड्राफ्ट को समापन सत्र के दौरान मंजूरी दी गई।

जम्मू में मेडिकल कॉलेज...

(पृष्ठ 6 का शेष)

कॉलेज के शिक्षा निदेशक ने कॉलेज बंद होने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कॉलेज बंद होने से शिक्षक काफी दुखी हैं। उनकी राय को भी नजरअंदाज किया गया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर मेडिकल कॉलेज पर इतनी राजनीति हो रही है, तो उस कॉलेज की कोई जरूरत नहीं है, छात्रों को दूसरे कॉलेजों में समायोजित कर दिया जायेगा। हैरानी की बात तो यह है कि उन्हें इसका विरोध करने के लिए कोई और दमदार तर्क नहीं मिला। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि कॉलेज बंद नहीं होगा।

कॉलेज के एक छात्र ने कहा कि हम सभी छात्र कॉलेज परिसर में एक साथ पढाई करते थे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। कुछ बाहरी लोगों के विरोध प्रदर्शन की वजह से हमारा भविष्य अधर में लटक गया। आजादी के बाद से कई शिक्षण संस्थान अनेक लोगों की मदद से तैयार हुए। वहां किसी धर्म या जाति का भेदभाव नहीं था। सभी धर्मों और जातियों के छात्रों को वहां पढ़ने का मौका मिला। क्योंकि तब शिक्षा का विस्तार ही लक्ष्य हुआ करता था। आज, सत्ताधारी पार्टियां अपने निहित स्वार्थ में धर्म को हथियार के रूप में एक-दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं। इस प्रकार एक-दूसरे में नफरत और जहर भरा जा रहा है। इससे धर्मनिरपेक्षता का घोर उल्लंघन हो रहा है।

जम्मू-कश्मीर में जब अनुच्छेद 370 हटाया गया था, तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमित शाह ने 'नये कश्मीर' का वादा किया था। क्या यही उनका नया कश्मीर है, जहां मेधा नहीं, बल्कि धार्मिक पहचान ही छात्रों की काबिलियत का पैमाना बन रही है! अपनी कड़ी मेहनत से जिन छात्रों को उस कॉलेज में दाखिले का मौका मिला था, हो सकता है कि उन्हें कुछ समय बाद दूसरे कॉलेज में प्रवेश मिल जाये, लेकिन क्या वे इस बात को भूल पायेंगे कि कॉलेज बंद होने की वजह सिर्फ अल्पसंख्यकों से नफरत थी?

वे भाजपा-आएसएस की साम्प्रदायिक नफरत के शिकार हुए हैं। उनका यह जख्म भरेगा कैसे? इन संगठनों द्वारा की जा रही ज्यादती राष्ट्रीय जीवन में एक बड़ा खतरा बनकर उभरी है। इसके खिलाफ शिक्षाप्रेमी और जनवाद पसंद तथा धर्मनिरपेक्ष लोगों को आगे आने की जरूरत है। उनका संगठित आन्दोलन ही भाजपा-आएसएस को इस तरह साम्प्रदायिकता का जहर फैलाने और पूरे देश को बदनाम करने से रोक सकता है। ●

बेंगलुरु: शिक्षा-विरोधी एनईपी-2020 की वैकल्पिक जन शिक्षा नीति के मसौदे पर एआईएसईसी द्वारा आयोजित जन संसद में शिरकत करते हुए देशभर से आये प्रतिनिधि

Printed and published by Com. Satyawan on behalf of the Central Committee of the Socialist Unity Centre of India (Communist) and printed at M/s Marutinandan Printers and Publishers, Shakti Complex,6/18, Sameypur Industrial Area, Delhi-110042 and published at 3A/38, WEA, Satnagar, Karol Bagh, New Delhi-110005.
Editor: Comrade Satyawan, Member, Central Committee, SUCI(C). **Phone No. : 9416763089, 9868350503** Email: **sarvaharadrishtikon@gmail.com**